लखनऊ

शनिवार, 30 मई, 2026

वर्ष : 11 । अंक: 273

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

"हार तो वो सबक है, जो आपको बेहतर होने का मौका देगी"

TODAY WEATHER

DAY 42° Hi

NIGHT 29° Low

संक्षेप

90 सेकेंड में 32 शब्दों की सही स्पेलिंग बताकर भारतीय मूल के श्रेय ने जीता खिताब, ईशान गुप्ता को दी मात

नई दिल्ली। कैलिफोर्निया के 14 वर्षीय भारतीय-अमेरिकी छात्र श्रेय पारिख ने शुक्रवार को स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीत ली। उन्होंने 90 सेकंड में 35 में से 32 शब्दों की सही स्पेलिंग बताई। डे क्रीक इंटरमीडिएट स्कूल के आठवीं कक्षा के छात्र पारिख ने 90 सेकंड की स्पेलिंग प्रतियोगिता में ब्रोमोक्रिप्टिन शब्द की सही स्पेलिंग बताकर न्यू जर्सी के जर्सी सिटी स्थित फ्रैंक आर कानवेल मिडिल स्कूल के सातवीं कक्षा के 12 वर्षीय ईशान गुप्ता को हराया। जार्जिया के टकर स्थित पीचट्री चार्टर मिडिल स्कूल के 12 वर्षीय सर्व धरवाने तीसरे स्थान पर रहे। ईशान को 25,000 अमेरिकी डॉलर और सर्व को 15,000 अमेरिकी डालर की पुरस्कार राशि मिली। पारिख ने 2024 में ब्रुहत सोमा द्वारा बनाए गए पिछले स्पेलिंग प्रतियोगिता के रिकार्ड को भी तोड़ दिया, जिन्होंने 30 में से 29 शब्दों की सही स्पेलिंग बताई थी।

श्रेय ने प्रतियोगिता जीतने के बाद कहा कि तेजी से वर्तनी का अभ्यास करना मेरा रोज का काम है। पारिख ने कई पुरस्कार जीते। इनमें 50,000 अमेरिकी डालर, एक स्मृति पदक, स्क्रिप्स कप, मेरियम-वेबस्टर से 2,500 अमेरिकी डॉलर, डेल्टा से 1,000 अमेरिकी डॉलर का फ्लाइट क्रेडिट और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से 400 अमेरिकी डालर की संदर्भ पुस्तकें शामिल हैं। पारिख प्रतियोगिता के 2024 संस्करण में भी फाइनलिस्ट थे।

यूएस में भारतीयों के साथ हो रहे नस्लवाद पर भारत ने क्या चेतावनी दी?

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत और अमेरिका के बीच होने वाली व्यापारिक वार्ता और अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ नस्लवाद के वायरल वीडियो पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कड़ा रुख दिखाया है। रणधीर जयसवाल ने कहा कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, अप्रैल के महीने में हमारी एक व्यापारिक टीम ने अमेरिका का दौरा किया था। अब हम अगले हफ्ते अमेरिका से एक टीम के भारत आने की उम्मीद कर रहे हैं, जहाँ इस बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। अब तक की बातचीत काफी सकारात्मक और रचनात्मक रही है। इस संबंध में जो भी आगे की जानकारी होगी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो (अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ नस्लवाद) पर उन्होंने आगे कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े आपके दूसरे सवाल पर मैं यही कहूँगा कि मैंने वह पोस्ट नहीं देखी है। हालांकि, किसी भी तरह का नस्लवाद, दुनिया में कहीं भी हो, पूरी तरह से अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अप्रैल महीने में अमेरिका से एक व्यापार दल भारत आया था। अब अगले सप्ताह अमेरिका से एक दल के भारत आने की उम्मीद है, जहां बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। अब तक हमारी बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक रही है। हम आपको इस संबंध में और अधिक जानकारी देते रहेंगे। इससे पहले भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने अमेरिका-भारत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना पर सकारात्मक संकेत देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है

'बार-बार कैसे लीक हो रहे हैं पेपर', नीट पेपर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल

नई दिल्ली, एजेंसी। NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाते हुए शुक्रवार को कहा कि वह इस पूरे मामले की जांच की खुद कुछ समय तक निगरानी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था 'नेशनल टेस्टिंग एजेंसी' (NTA) को कड़ी फटकार लगाते हुए इस घटना को युवाओं के लिए बेहद दुखत बताते हुए कहा कि जो हुआ वह बेहद दुखद है, युवाओं को इस तरह निराश नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने (केंद्र सरकार) शिक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह एक अलग हलफनामा दायर करे, जिसमें एक ऐसी व्यवस्था बनाने का ब्योरा दिया जाए जिसके तहत NEET परीक्षाओं को आयोजित

करने और पूरा करने की प्रक्रिया को NTA द्वारा हर साल संस्थागत रूप से संचालित किया जा सके। साथ ही इस बात पर अपना जवाब दाखिल करे कि NTA को कैसे मजबूत बनाया जाए और NEET परीक्षा को कैसे पूरी तरह से सुरक्षित बनाया जाए। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने साफ कहा कि इस हलफनामे में यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि विशेष कर्मियों की तैनाती और विशेषज्ञों की एक व्यापक टीम के माध्यम से NTA के भीतर संस्थागत अनुभव और विशेषज्ञता को कैसे विकसित किया जाएगा।

कोर्ट ने केंद्र और NTA को दिया छह सप्ताह का दिया समय

कोर्ट ने टिप्पणी की कि इस प्रयास का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि NTA के पास 2024 और 2026 की NEET परीक्षा विवादों जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक भौतिक और बौद्धिक संसाधन मौजूद हों। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और NTA को अपनी कार्ययोजना पेश करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है। सुनवाई के दौरान पीठ ने NTA और इस मामले के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन द्वारा दाखिल किए गए जवाबों और हलफनामों का संज्ञान लिया।

तय होनी चाहिए जिम्मेदारी

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने से रोकने के लिए सरकार और सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि बार-बार कैसे पेपर लीक हो जा रहे हैं। अगर ऐसी घटना दोबारा होती है। तो उसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

पीएम मोदी खुद रख रहें नजर

इस दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को आश्वस्त करते हुए कोर्ट को सूचित किया कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद देश के प्रधानमंत्री इस पूरे मुद्दे पर सीधे नजर रख रहे हैं और सरकार परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए पूरी तरह गंभीर है।

विनम्रता, क्षमाशीलता और उत्तम आचरण ही व्यक्तित्व के सच्चे आभूषण हैं : पीएम

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विनम्रता और क्षमाशीलता को लेकर संस्कृत सुभाषित शेयर किया। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि विनम्रता, क्षमाशीलता और उत्तम आचरण ही व्यक्तित्व के सच्चे आभूषण हैं। इन गुणों के साथ ही आज देशवासी विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में निरंतर जुटे हैं। प्रधानमंत्री ने तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता। भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत।। संस्कृत श्लोक भी साझा किया है। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है कि तेजस्विता, क्षमाशीलता, अदम्य धैर्य, आचरण की पवित्रता, राष्ट्र के प्रति निष्कपट भाव तथा अहंकाररहित व्यक्तित्व ये सभी गुण दैवी संपदा को प्राप्त व्यक्तित्व के लक्षण कहे गए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री की ओर से गुरुवार

को भी सुभाषित शेयर किया गया था। उन्होंने लिखा था कि महान क्रांतिकारी और प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक वीर सावरकर जी को उनकी जयंती पर सादर नमन! वीरता और बौद्धिकता से भरा उनका व्यक्तित्व देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। पीएम ने अनन्तोद्भूतभूतौघसङ्कुले भूतलेऽखिले। शस्त्रे शास्त्रे त्रिचतुराश्चतुरा यदि मादृशाः।। श्लोक साझा किया था, जिसका हिंदी अर्थ है कि संसार में अनेक लोग केवल ज्ञान या केवल शक्ति के लिए प्रसिद्ध होते हैं, किंतु वास्तव में वे धीर गंभीर व्यक्तित्व अत्यंत विरले होते हैं जो ज्ञान और पराक्रम दोनों से युक्त हों।

पांच दिन की हीटवेव बन सकती है 30 हजार मौतों की वजह, भीषण गर्मी के बीच आई डराने वाली रिपोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। देश में लगातार बढ़ती भीषण गर्मी अब सिर्फ मौसम की परेशानी नहीं, बल्कि बड़ा स्वास्थ्य संकट बनती जा रही है। एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि भारत में एक दिन की अत्यधिक गर्मी से करीब 3400 अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं, जबकि लगातार पांच दिन तक चलने वाली हीटवेव लगभग 30 हजार लोगों की जान ले सकती है। यह अध्ययन अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के इंडिया एनर्जी एंड क्लाइमेट सेंटर के शोधकर्ताओं ने किया है। रिपोर्ट ऐसे समय आई है, जब उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है और लोग भीषण लू का सामना कर रहे हैं। शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में

गर्मी से होने वाली मौतों का आंकड़ा और तेजी से बढ़ सकता है। शोधकर्ताओं पियूष नारंग और अशोक गाडगिल ने भारत के 10 शहरों में गर्मी से होने वाली मौतों के पुराने आंकड़ों का विश्लेषण कर देशभर के जिलों के लिए अनुमान तैयार किया। यह अध्ययन 'फ्रंटियर्स इन एनवायरमेंटल हेल्थ' जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इसमें 'एक्सेस डेथ' यानी अतिरिक्त मौतों का आकलन किया गया।

किन राज्यों पर सबसे ज्यादा खतरा बताया गया?

अध्ययन में बताया गया है कि जिन राज्यों की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर है, वहीं गर्मी से मौतों का खतरा सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात देश की कुल अतिरिक्त मौतों का 66 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं, जबकि देश की जीडीपी में इनकी हिस्सेदारी केवल 29 प्रतिशत है। शोधकर्ताओं ने कहा कि यह असमानता बेहद चिंताजनक है। इसका मतलब है कि गरीब और कम संसाधनों वाले राज्य गर्मी का सबसे ज्यादा नुकसान झेल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश के शीर्ष 100 जिले, जहां लगभग एक-तिहाई आबादी रहती है, पांच दिन की हीटवेव के दौरान कुल अनुमानित मौतों का 44 प्रतिशत हिस्सा बन सकते हैं। इससे साफ है कि हीटवेव का खतरा केवल जनसंख्या पर नहीं, बल्कि आर्थिक और स्वास्थ्य ढांचे की कमजोरी पर भी निर्भर करता है।

'मेरी बेटी ने भी 8वीं तक मराठी पढ़ी', सीबीएसई की तीन-भाषा नीति पर घमासान, धर्मेंद्र प्रधान ने किया बचाव

नई दिल्ली, एजेंसी। कक्षा 9 के छात्रों के लिए CBSE की नई तीन-भाषा नीति को लेकर देशभर में जारी बहस के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस नीति का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा, उसका पूरी तरह पालन करेगी।

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा, हम वही करेंगे।' उन्होंने यह बयान उन सवालों के जवाब में दिया, जो अभिभावकों और छात्रों की ओर से नई भाषा नीति को लेकर उठाए जा रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि सीबीएसई ने कोई पूरी तरह नई व्यवस्था लागू नहीं की है। उनके मुताबिक देश के लगभग 99 प्रतिशत सीबीएसई स्कूलों में छात्र कक्षा 6 से 8

तक अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा पढ़ते हैं और नया सर्कुलर सिर्फ इसी व्यवस्था को कक्षा 9 तक जारी रखने की बात कहता है।

बेटी का उदाहरण देकर समझाई नीति

धर्मेंद्र प्रधान ने बातचीत के दौरान अपना निजी उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा, 'मेरी बेटी ने भी 8वीं तक मराठी पढ़ी है।' उनका कहना था कि भारत में मातृभाषा में पढ़ाई करना कोई नई बात नहीं है और नई शिक्षा नीति 2020 में भी इसे बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपनी भाषा और संस्कृति से जोड़ना जरूरी है। सरकार का उद्देश्य भारतीय भाषाओं को मजबूत करना और छात्रों को बहुभाषी शिक्षा से जोड़ना है। सीबीएसई ने हाल ही में घोषणा की थी कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 9 के छात्रों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं शामिल होंगी। इसी फैसले के बाद विवाद शुरू हुआ।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

नई नीति को लेकर कई अभिभावकों, छात्रों और शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाओं में कहा गया है कि कई स्कूलों में पर्याप्त भाषा शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं और इससे छात्रों पर अतिरिक्त पढ़ाई का दबाव बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, सीबीएसई और एनसीईआरटी से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना सिद्धांत रूप में अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन इसे लागू करने से पहले व्यावहारिक और प्रशासनिक चुनौतियों को भी देखना जरूरी है। फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और आने वाले समय में इस पर आगे की सुनवाई के बाद नीति को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो सकती है।

दालमण्डी में फिर चलेगा बुलडोजर, दो दिन में गिराए जाएंगे 18 भवन

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

वाराणसी। दालमण्डी में चौड़ीकरण परियोजना को लेकर प्रशासन एक बार फिर सक्रिय हो गया है। त्यौहारों और गर्मी की छुट्टियों के चलते क्षेत्र में बढ़ी भीड़ कम होने के बाद अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई दोबारा शुरू की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी की ओर से इलाके में मुनादी कराकर स्थानीय लोगों को कार्रवाई की जानकारी दी गई।

मुनादी के दौरान बताया गया कि 30 और 31 मई 2026 को दालमण्डी चौड़ीकरण योजना के तहत पहले से क्रय किए जा चुके भवनों को गिराया जाएगा। प्रशासन द्वारा तय समय के अनुसार दोनों दिन दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक ध्वस्तीकरण अभियान चलाया जाएगा। जानकारी के अनुसार कुल 18 भवनों को जमींदोज किया जाना है। इनमें 30 मई को 5 भवनों पर कार्रवाई होगी, जबकि 31 मई को 13 भवन गिराए जाएंगे।

प्रशासन ने संबंधित भवन स्वामियों और आसपास के लोगों से सहयोग की अपील करते हुए निर्धारित समय में क्षेत्र खाली रखने को कहा है। दालमण्डी चौड़ीकरण परियोजना को शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने और क्षेत्र में बढ़ते दबाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि परियोजना पूरी होने के बाद क्षेत्र में आवागमन पहले की तुलना में अधिक सुगम होगा। इस ध्वस्तीकरण अभियान का उद्देश्य दालमण्डी क्षेत्र में यातायात की समस्या को हल करना और क्षेत्र की चौड़ाई को बढ़ाना है, जिससे आने वाले समय में यातायात की स्थिति में सुधार हो सके। प्रशासन ने स्थानीय निवासियों से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया में सहयोग करें और निर्धारित समय पर

राहुल गांधी का दिल्ली में ऑटो चालकों संग लंच, बढ़ती ईंधन की कीमत की सुनी चिंताएं

नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को मध्य दिल्ली में ऑटो रिक्शा चालकों से मुलाकात की और उनके साथ दोपहर का भोजन किया। यह अनौपचारिक बातचीत राष्ट्रीय राजधानी में परिवहन कर्मचारियों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने के उद्देश्य से की गई थी। राहुल गांधी ने बंगाली मार्केट के पास टोडरमल रोड पर लगभग आधा घंटा बिताया, जहां उन्होंने टोडरमल पार्क में जमा हुए चालकों से बातचीत की। इस दौरान, उन्होंने ऑटो रिक्शा चालकों से सीधे बात की और बढ़ते खर्चों, ईंधन की कीमतों और घटती आय के बारे में उनकी चिंताओं को सुना। इस बातचीत के तहत कांग्रेस सांसद को एक ऑटो चालक के साथ दोपहर का भोजन करते हुए भी देखा गया। यह बातचीत बंगाली मार्केट के

पास टोडरमल पार्क में हुई, जो स्थानीय परिवहन कर्मचारियों और यात्रियों द्वारा अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला एक व्यस्त इलाका है। खबरों के अनुसार, राहुल गांधी ने ड्राइवरों से उनकी रोजमर्रा की कठिनाइयों और परिवहन क्षेत्र को प्रभावित करने वाले वित्तीय दबावों के बारे में बातचीत की। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दिल्ली और आसपास के शहरों में वाणिज्यिक वाहन संचालक बढ़ती परिचालन लागत और अपर्याप्त किराया संशोधन को लेकर चिंता जता रहे हैं। राहुल गांधी ने हाल के वर्षों में अक्सर इसी तरह के जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें उन्होंने श्रमिकों, मजदूरों, डिलीवरी कर्मियों और ड्राइवरों से मिलकर आजीविका संबंधी मुद्दों पर चर्चा की है। यह बैठक दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में परिवहन यूनियनों द्वारा 21 से 23 मई के बीच की गई व्यापक हड़ताल के कुछ ही दिनों बाद हो रही है। इस विरोध प्रदर्शन के कारण कैब और ऑटो-रिक्शा सहित कई सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बाधित हुईं, जिससे एनसीआर भर के यात्रियों को असुविधा हुई।

महाराष्ट्र में 16 लोगों की मौत से हड़कंप, लोगों ने जहरीली शराब बताई वजह, पुलिस ने नकारा

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में पिछले कुछ दिनों में 16 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों के बीच इन मौतों को जहरीली शराब से जोड़कर देखा जा रहा है, हालांकि पुलिस ने फिलहाल इस दावे से इनकार किया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौतों की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। मामले की जांच जारी है।

जानकारी के मुताबिक, पुणे-मुंबई हाईवे स्थित पिंपरी-चिंचवड़ के फुगेवाड़ी इलाके में एक ही दिन में 7 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद 4 और लोगों की जान चली गई। वहीं पुणे शहर में पहले 3 मौतें सामने आई थीं, जिनकी संख्या अब बढ़कर 5 हो गई है। कुछ अन्य लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है। फुगेवाड़ी क्षेत्र में अवैध हाथभट्टी और देसी शराब के अड्डों के संचालन को लेकर स्थानीय नागरिकों में नाराजगी है। लोगों के बीच चर्चा है कि मौतों के पीछे जहरीली शराब हो सकती है। हालांकि, दापोडी पुलिस ने इन दावों को अफवाह बताते हुए कहा है कि शुरुआती जांच में सभी मौतें अलग-अलग कारणों से हुई प्रतीत होती हैं। पुलिस के अनुसार, पांडुरंग फुगे (57) की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई। विजय राठौड़ (31) और राजेंद्र राठौड़ (34) नामक दो सगे भाइयों की मौत हार्ट अटैक से होने की आशंका जताई गई है। राजेंद्र राजपूत (51) की मौत बाथरूम में चक्कर खाकर गिरने से हुई बताई गई है।

कंफर्म टिकट होने पर भी सीट नहीं मिली, एक उपभोक्ता अदालत ने भारतीय रेलवे को भरना होगा 35,000 से अधिक का जुर्माना

नई दिल्ली, एजेंसी। एक उपभोक्ता अदालत ने भारतीय रेलवे को यात्रियों को आरक्षित बर्थ उपलब्ध न कराने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। भोजपुर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रेलवे को उन चार यात्रियों को 20,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है, जिन्हें पूरी ट्रेन यात्रा खड़े होकर पूरी करनी पड़ी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, यह शिकायत तब सामने आई जब विंध्याचल (मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश) से आरा (भोजपुर, बिहार) जा रही एलटीटी पटना एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे चार यात्रियों ने ट्रेन में चढ़ते समय पाया कि उनकी आरक्षित बर्थ पर रेलवे कर्मचारी बैठे हुए थे।

शिकायत में कहा गया है कि यात्रियों ने कर्मचारियों से अपनी आरक्षित बर्थ खाली करने का अनुरोध किया, लेकिन उन्हें उनकी सीट नहीं दी गई। कृष्णा

प्रताप सिंह (अध्यक्ष) और कमल किशोर सिंह (सदस्य) की पीठ ने पाया कि रेलवे की सेवा में खामियों के कारण यात्रियों को ₹मानसिक, शारीरिक और आर्थिक उत्पीड़न₹ का सामना करना पड़ा। पीठ ने उत्तर मध्य रेलवे और रेल मंत्रालय को आदेश दिया कि वे बुकिंग राशि 1,876.80 रुपये 8% वार्षिक ब्याज सहित वापस करें और 20,000 रुपये मुआवजे के रूप में तथा 15,000 रुपये मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 60 दिनों के भीतर भुगतान करें।

आयोग ने आगे कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से 10% वार्षिक ब्याज सहित राशि वसूलने का हकदार होगा। शिकायत के अनुसार, यात्रियों ने पहले रेलवे हेल्पलाइन और रेलवे सेवा एवं रेल मंत्रालय सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया था। हालांकि, एसएमएस के माध्यम से शिकायत संदर्भ संख्या प्राप्त होने के बावजूद, यात्रियों ने आरोप लगाया कि यात्रा के दौरान कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

यात्रियों ने यह भी बताया कि जब बक्सर स्टेशन पर एक टीटीई (ट्रेन का कर्मचारी) उपस्थित हुआ, तो उन्होंने फिर से यह मुद्दा उठाया, लेकिन कथित तौर पर उन्हें ट्रेन में भारी भीड़ के कारण संभालने के लिए कहा गया। आयोग के समक्ष रेलवे ने तर्क दिया कि कानून-व्यवस्था से संबंधित विवाद सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) के अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि रेलवे प्रशासन के। रिपोर्टों के अनुसार, रेलवे ने सेवा में किसी भी प्रकार की कमी से इनकार किया और दावा किया कि शिकायत पर उचित कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है।

भारत में घुसपैठ पर बड़ा एक्शन प्लान : 'सख्त कानूनों की हो सकती है सिफारिश', जस्टिस नावलेकर ने दिया संकेत

इंदौर। देश में घुसपैठ के कारण हो रहे जनसांख्यिकीय बदलाव को लेकर गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष और पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर ने इसे एक गंभीर और बड़ी चुनौती बताया है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर समिति केंद्र सरकार को और सख्त कानून लागू करने की सिफारिश कर सकती है। जस्टिस नावलेकर ने कहा कि अवैध घुसपैठ केवल सीमावर्ती क्षेत्रों तक सीमित समस्या नहीं है, बल्कि इसका असर अब शहरी इलाकों, औद्योगिक क्षेत्रों और सामाजिक-आर्थिक रूप से संवेदनशील हिस्सों तक फैल रहा है।

एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाती है, लेकिन घुसपैठ के कारण लाभार्थियों की संख्या बढ़ने से वास्तविक जरूरतमंदों का हिस्सा प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति न केवल आर्थिक दबाव बढ़ाती है, बल्कि सामाजिक संतुलन को भी प्रभावित करती है।

जस्टिस नावलेकर ने स्पष्ट कहा कि अगर समिति को लगता है कि मौजूदा कानून पर्याप्त नहीं हैं, तो वह सरकार को और कड़े कानूनों की सिफारिश कर सकती है। उन्होंने कहा कि किसी भी अपराध को रोकने के लिए सिर्फ कानून ही नहीं, बल्कि उनका सख्त क्रियान्वयन भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब सजा का डर होगा, तभी गलत कामों में कमी आएगी।

घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलाव पर व्यापक अध्ययन

गृह मंत्रालय द्वारा गठित इस समिति का उद्देश्य देश के अलग-अलग हिस्सों में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का वैज्ञानिक अध्ययन करना है। समिति यह भी जांच करेगी कि इन बदलावों के पीछे क्या कारण हैं और उनके समाधान के लिए कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। जस्टिस नावलेकर ने कहा कि भारतीय कानून शरणार्थियों और अवैध घुसपैठियों के बीच स्पष्ट अंतर करता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह समस्या केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि कई विकसित देश भी इससे जूझ रहे हैं।

इस उच्च स्तरीय समिति में पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और डॉ. शमिका रवि भी शामिल हैं। समिति को एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर छह महीने का विस्तार दिया जा सकता है।

पॉक्सो मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को सुप्रीम कोर्ट से राहत, बरकरार रहेगी अग्रिम जमानत

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

प्रयागराज। सुप्रीम कोर्ट ने आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के 25 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इसके प्रयागराज के POCSO मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को अग्रिम जमानत दी गई थी। ये मामला नाबालिगों के यौन शोषण से जुड़ा हुआ है। इस मामले में अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत बरकरार रहेगी। जस्टिस एम।एम। सुंदरेश और जस्टिस एन।के। सिंह की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। इस मामले में शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने AOR सौरभ अजय गुप्ता के जरिए यह याचिका दायर की थी। याचिका में यह तर्क दिया गया था कि हाई कोर्ट ने स्वामी पर लगे आरोपों की गंभीरता पर ठीक से विचार नहीं किया।

जस्टिस सुंदरेश ने याचिकाकर्ता से पूछा कि नाबालिगों के शोषण के बारे में जानकारी होने का दावा करने के बावजूद, पुलिस के पास जाने में इतनी देरी क्यों की गई? हाई कोर्ट ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य को आंशिक रूप से इस आधार पर राहत दी थी, जिसे कोर्ट ने नाबालिग पीड़ितों का 'असामान्य' व्यवहार बताया था, क्योंकि पीड़ितों ने अपराधों के बारे में अपने स्वाभाविक अभिभावकों के बजाय एक अजनबी को बताने का रास्ता चुना था।

गिरफ्तारी में क्यों हुई 6 दिन की देरी?

अपने 22 पन्नों के आदेश में हाई कोर्ट ने राज्य की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि POCSO एक्ट की धारा 29 के तहत आरोपी के खिलाफ अपराध की एक कानूनी धारणा होती है। बेंच ने साफ किया कि ये धारणा गिरफ्तारी से पहले के चरण में यानी आरोप तय होने से पहले, लागू नहीं की जा सकती। बेंच ने अपराध के बारे में पुलिस को जानकारी देने में हुई 6 दिन की देरी पर भी प्रकाश डाला। पीड़ितों ने 18 जनवरी, 2026 को ब्रह्मचारी को इस बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने 24 जनवरी तक पुलिस से संपर्क नहीं किया। उनका दावा था कि वे एक पूजा में व्यस्त थे। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि पूजा/यज्ञ में व्यस्त होने का दावा करने के बावजूद, शिकायतकर्ता (ब्रह्मचारी) ने 21 जनवरी को BNS की धारा 109 और अन्य धाराओं के तहत एक अलग घटना के संबंध में एक अलग अर्जी दायर की थी। कोर्ट ने इस मामले में मीडिया की दखलंदाजी पर भी कड़ी आपत्ति जताई थी।

सत्यधाम आश्रम के वार्षिकोत्सव में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब

सुल्तानपुर। जिले के कोइरीपुर रेलवे स्टेशन के समीप स्थित सिंहौली गांव के सत्यधाम आश्रम में वार्षिकोत्सव के अवसर पर दो दिवसीय संत समागम एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से आए संत-महात्माओं और हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। आयोजन के दौरान आध्यात्मिक प्रवचन, सत्संग, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं भंडारे का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ संतों के चरण प्रच्छालन एवं माल्यार्पण के साथ हुआ। सत्यधाम के गद्दीधीश आचार्य सत्यसमदर्शी देवेन्द्र कविराजदेव जी महाराज ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि निज स्वरूप का ज्ञान ही परमबोध है। उन्होंने संत दर्शन, भक्ति, मुक्ति तथा जन-जीव कल्याण के महत्व पर प्रकाश डाला। समागम में गुरु मां उत्तम साहिब, संत निर्मल जी, संत शत्रुघ्न जी, संत कर्मेंद्र जी, संत लक्ष्मण दास, सहित कई संतों ने सत्संग के माध्यम से श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक संदेश दिए।

शादी के 26वें दिन पति ने दी जान : शाम में पत्नी ने की ऐसी हरकत, जो युवक से न हुई बर्दाश्त, रात में लगा ली फांसी

आर्यावर्त संवाददाता

आदमपुर (अमरोहा)। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां शादी के 25 दिन बाद पति से कहासुनी होने पर नवविवाहिता ने ऐसे कड़वे शब्दों का प्रयोग किया, जिन्हें पति बर्दाश्त नहीं कर सका और फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने बिना कार्रवाई शव का अंतिम संस्कार कर दिया।

आदमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक साप्ताहिक बाजार में सब्जी बेचने का काम करता था। 25 दिन पहले उसकी शादी सैदनगली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती से हुई थी। बताते हैं कि नवदंपती में शादी के दो दिन बाद से ही किसी बात को लेकर मनमुटाव शुरू हो गया था। बुधवार शाम को भी दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। परिजनों ने बताया कि कहासुनी के दौरान नवविवाहिता ने गुस्से में पति को ऐसा ताना मारा दिया, जिन्हें वह बर्दाश्त नहीं कर सका और रात में किसी समय कमरे में ही फंदे पर लगाकर आत्महत्या कर दी। बृहस्पतिवार की सुबह को कमरे में उसका शव फंदे पर लटका मिला। युवक दो भाइयों में छोटा था। परिजनों ने बिना कार्रवाई शव का अंतिम संस्कार कर दिया। सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि इस मामले में कोई सूचना नहीं मिली है।

जल जीवन मिशन के सामान में लगी रहस्यमयी आग, करोड़ों के 'खेल' पर उठे बड़े सवाल

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

बल्दीराय/सुलतानपुर। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना के तहत घर-घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए रखे गए पाइप, मशीनरी और अन्य उपकरणों में गुरुवार दोपहर संदिग्ध परिस्थितियों में लगी भीषण आग ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। घटना बल्दीराय थाना क्षेत्र के देहली बाजार चौकी अंतर्गत कनेहटी गांव के पास की है, जहां सड़क किनारे रखे आनंद इंटरप्राइजेज के लाखों रुपये के सामान देखते ही देखते आग की लपटों में समा गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोपहर करीब 1.00 बजे अचानक धुएं का गुबार उठने लगा और कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी तेज थी कि मौके पर रखे एमडीपी पाइप, प्लास्टिक पाइप, कंप्रेशर मशीन, टैंक सामग्री, प्लाई बोर्ड, मशीनरी पार्ट्स तथा बांस-बल्लियां धू-धू कर जलने लगीं। घटना की सूचना मिलते ही पीआरबी 6101 मौके पर पहुंची। चौकी प्रभारी महेंद्र कुमार राय पुलिस बल के साथ राहत एवं सुरक्षा कार्य में जुट गए। बाद में फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि तब तक अधिकांश सामान जलकर राख हो चुका था।

आग पर उठे सवाल

घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि लोहे के कंप्रेशर, भारी मशीनरी और मोटे पाइपों में इतनी तेजी से आग लगना सामान्य घटना नहीं प्रतीत होती। लोगों के बीच यह आशंका भी जोर पकड़ रही है कि कहीं जल जीवन मिशन में हुए किसी कथित भ्रष्टाचार, गड़बड़ी या सामान के हिसाब-किताब पर पर्दा डालने के लिए आग जानबूझकर तो नहीं लगाई गई। ग्रामीणों का कहना है कि इसी स्थान से आसपास के कई गांवों में जल जीवन मिशन की सामग्री की सप्लाई की जाती थी और यहां करोड़ों रुपये के सामान का भंडारण रहता था। ऐसे में अचानक लगी आग ने न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि योजना की पारदर्शिता को लेकर भी गंभीर संदेह पैदा कर दिया है।

जांच की मांग तेज

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि आग लगने के वास्तविक कारणों का खुलासा होना चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह महज हादसा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है। पुलिस और प्रशासन फिलहाल मामले की जांच में जुटा हुआ है।

गोमती मित्र मंडल समिति होगी लखनऊ में सम्मानित

सुलतानपुर। माय होम इंडिया परिवार द्वारा 30 मई दिन शनिवार को लखनऊ के छत्रपति शाहूजी महाराज भागीदारी भवन में आयोजित होने वाले स्वातंत्र्यवीर सावरकर जयंती महोत्सव में पर्यावरण एवं गोमती स्वच्छता के लिए किए गए व किये जा रहे उल्लेखनीय कार्यों के लिए विशिष्ट अतिथि पूर्व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रो.डॉक्टर सतीश द्विवेदी, मुख्य वक्ता पूर्व राष्ट्रीय सचिव भाजपा एवं संस्थापक माय होम इंडिया सुनील देवधर व कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कृपा शंकर सिंह पूर्व गृह राज्य मंत्री महाराष्ट्र की उपस्थिति में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ असीम अरुण करेंगे गोमती मित्र मंडल समिति कुशभवनपुर को सम्मानित, उपरोक्त कार्यक्रम में विशेष भूमिका का निर्वहन करने वाले आलोक रंजन द्वारा आयोजक मंडल को गोमती मित्र मंडल द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तार से चर्चा करने के बाद आयोजक मंडल द्वारा यह निर्णय लिया गया है।

प्रयागराज में बदला मौसम, चार घंटे में 61 मिमी बारिश से मौसम सुहावना, तपती गर्मी काफूर तो मिली राहत

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

प्रयागराज। पिछले 10 दिनों से आग उगलती गर्मी से जूझ रहे प्रयागराज में गुरुवार की रात मौसम ने ऐसा पलटा खाया कि लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। दिनभर सूरज की तपिश से झुलसने के बाद शहर सोने गया था, लेकिन आधी रात के बाद बादलों ने ऐसी दस्तक दी कि सुबह का नजारा पूरी तरह बदल चुका था।

रात करीब एक बजे अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। कुछ ही देर में आसमान में बिजली चमकी और गरजते बादलों के बीच बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते बूंदों ने रफ्तार पकड़ी और पूरी रात तेज से मध्यम बारिश का सिलसिला चलता रहा। सुबह जब लोग जागे तो तपिश की जगह ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। पेड़ धुले हुए दिखे, सड़कों पर पानी बह रहा था और वातावरण में वह ताजगी थी जिसका लोग कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। कई जगह सड़क किनारे जलभराव भी हो गया।

नौतपा शुरू होने के पांचवें दिन ही मौसम का मिजाज बदल गया। गुरुवार यानी 28 मई की रात करीब एक बजे से सुबह पांच बजे तक 61 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस बारिश का असर तापमान पर भी साफ दिखाई दिया। 28 मई को न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस था, जो आज शुक्रवार 29 मई की सुबह घटकर 21.9 डिग्री सेल्सियस रह गया। यानी महज एक रात में पारा 6.3 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया।

गर्मी और उमस से मिली राहत

पिछले कई दिनों से अधिकतम तापमान 47 डिग्री के आसपास पहुंच रहा था और शहर लू की चपेट में था। ऐसे में यह बारिश किसी प्राकृतिक राहत पैकेज से कम नहीं रही। बिजली कटौती और उमस से परेशान लोगों के लिए यह मौसम किसी राहत भरे संदेश की तरह आया। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि खेती के लिए यह वर्षा बेहद लाभदायक साबित हो सकती है। जमीन की जलधारण क्षमता भी बेहतर होगी।

कुछ दिन गर्मी से रहेगी राहत

मौसम विभाग का अनुमान है कि राहत का यह दौर अभी कुछ दिन और जारी रहेगा। शनिवार को भी बारिश और गरज-चमक की संभावना है। 31 मई और 1 जून को भी एक-दो दौर की बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हालांकि दो जून यानी नौतपा के मौसम फिर साफ होने लगेगा और तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है।

नौतपा में बारिश से अंबेडकरनगर के लोगों को मिली राहत, बिजली गिरने से किसान की मौत

आर्यावर्त संवाददाता

अंबेडकरनगर। नौतपा में शुक्रवार की सुबह मौसम बदल गया। गरज-चमक संग बारिश शुरू हो गई। बिजली गिरने से किसान की मौत हो गई। राजस्व टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। प्रभावित परिवार को अहेतुक सहायता दिलाने का भरोसा दिलाया है। वहीं कुछेक स्थान पर जलभराव की समस्या दिखी। वहीं, आंधी से पेड़ गिरने से बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हो गए।

नौतपा में कई दिनों से भीषण गर्मी का प्रकोप जारी था। दिन में तेज धूप और रात में उमस के कारण लोग बेहाल थे। शुक्रवार को भोर में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। गर्मी से लोगों को राहत मिली। अकबरपुर के अयोध्या मार्ग और उसरहवा मुहल्ले में नालियों की सफाई न होने से जलभराव हो गया।

टांडा तहसील के मीठेपुर किसान इंद्रजीत सुबह पशुओं को चराने के लिए भड़सारी गांव के गोशाला के गए थे। खेत में ही वह पशुओं के साथ थे। इसी दौरान बिजली गिरने से इंद्रजीत पाल की मौत हो गई।

किसान के चार बेटी व तीन बेटे के सिर से पिता का साया छिन गया। तहसील प्रशासन व इब्राहिमपुर पुलिस ने घटना स्थल व किसान के घर पहुंचकर स्वजन को ढांढस बंधाते हुए अहेतुक सहायता का आश्वासन दिया। थानाध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने बताया कि विधिक कार्रवाई की जा रही है।

संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत

बल्दीराय/सुलतानपुर। बल्दीराय थाना क्षेत्र के ग्राम सझौंवा मजरे बहुरांवा में दोपहर एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही बल्दीराय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार मृतका लक्ष्मी (27 वर्ष) पत्नी रविकुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तब तक परिजन महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जा चुके थे। बल्दीराय पुलिस घटना स्थल का निरीक्षण के बाद अस्पताल पहुंच कर मृतका के शव का पंचनामा करवाने के बाद शव को पीएम के लिए मर्चरी हाऊस भेज दिया। कूरेभार थाना क्षेत्र के पूरे सागर मजरे पुरखीपुर निवासी मृतका के भाई कप्तान ने आरोप लगाया कि उसकी बहन की शादी करीब 15 वर्ष पूर्व रविकुमार के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग उसे प्रताड़ित करते थे। भाई का आरोप है कि बृहस्पतिवार को भी लक्ष्मी के साथ मारपीट की गई, जिसके चलते उसकी मौत हो गई।

GDA में अब घर बैठे जमा करें शुल्क, नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) के आवंटियों को अब शुल्क जमा करने के लिए दफ्तरों और बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जीडीए ने आनलाइन चालान प्रबंधन प्रणाली लागू कर दी है, जिससे प्लाट, फ्लैट, दुकान या अन्य संपत्ति के आवंटी घर बैठे आनलाइन शुल्क जमा कर सकेंगे। नई व्यवस्था से समय की बचत होने के साथ भुगतान प्रक्रिया पहले से अधिक आसान और पारदर्शी बनने की उम्मीद है।

अब तक आवंटियों को किस्त, शुल्क या अन्य देय राशि जमा करने के लिए कई बार कार्यालय या बैंक का रुख करना पड़ता था। लंबी लाइन, कागजी प्रक्रिया और भुगतान की स्थिति जानने में दिक्कतें आम थीं। नई प्रणाली लागू होने के बाद यह प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी। आवंटी अपने मोबाइल या कंप्यूटर से आनलाइन चालान तैयार कर भुगतान कर सकेंगे। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आवंटियों को हर छोटे काम के लिए जीडीए कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। भुगतान के तुरंत बाद डिजिटल रसीद उपलब्ध होगी, जिसे जरूरत पड़ने पर डाउनलोड या प्रिंट भी किया जा सकेगा। इससे भुगतान को लेकर विवाद या रिकार्ड गुम होने जैसी समस्याएं कम होंगी। नई प्रणाली से आवंटी अपने बकाया शुल्क, किस्त और भुगतान की स्थिति भी आसानी से देख सकेंगे। किस तारीख को कितना भुगतान किया गया और कितना बाकी है, इसकी जानकारी एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध रहेगी। इससे पुराने रिकार्ड तलाशने की परेशानी कम होगी। ऑनलाइन व्यवस्था से गलत एंट्री या मैनुअल गड़बड़ी की संभावना भी घटेगी, क्योंकि भुगतान प्रक्रिया डिजिटल और स्वतः संचालित होगी। आवंटी 24 घंटे कभी भी भुगतान कर सकेंगे और कार्यालय समय पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा भुगतान सफल होने या बकाया राशि से जुड़ी सूचना मोबाइल या ईमेल पर मिलने की सुविधा भी उपयोगी साबित हो सकती है। जीडीए की इस पहल को आम लोगों के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है। खासकर उन आवंटियों के लिए, जिन्हें शुल्क जमा करने या भुगतान संबंधी जानकारी लेने के लिए बार-बार कार्यालय जाना पड़ता था। नई व्यवस्था से समय, मेहनत और खर्च तीनों की बचत होने की उम्मीद है।

हिंदू नाम बता बिलाल ने की लड़की से दोस्ती, ईद पर होटल में बुलाया ; सच सामने आया तो हुआ बखेड़ा

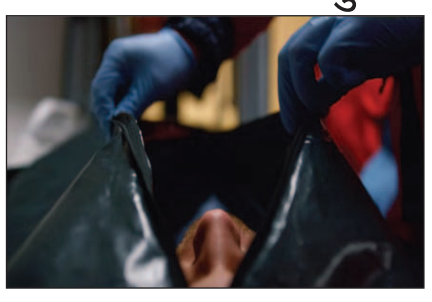

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ। गुरुग्राम की लड़की को हिंदू नाम बताकर प्रेमजाल में फंसाया। दोस्ती का वास्ता देकर बिजली बंबा स्थित होटल में बुला लिया। यहां पर लड़की को सच्चाई पता चली। उसकी शिकायत पर पुलिस ने होटल से दोनों को बरामद कर थाने ले आई। युवती को उसके स्वजन के सिपुर्द कर दिया। आरोपित के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की गई। पूर्वा इलाही बक्स निवासी बिलाल कपड़ों की फेरी लगाने का काम करता है।

इंस्टाग्राम पर बिलाल ने हिंदू नाम से आइडी बना रखी है। उसने गुरुग्राम की युवती से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की। उसके बाद दिल्ली के क्लब में बुलाकर शादी के सपने दिखाए। झांसे में लेकर बकरीद के मौके पर युवती को गुरुग्राम से मेरठ बुलाया। उसके बाद बिजली बंबा स्थित होटल में ले गया। वहां पर युवती को बिलाल की सच्चाई के बारे में जानकारी मिली। उसके बाद युवती ने मामले की जानकारी पुलिस को दी।

पुलिस ने होटल से दोनों को बरामद कर लिया। ब्रह्मपुरी एसओ राजेश कांबोज ने बताया कि युवती को उसके स्वजन के सिपुर्द कर दिया। बिलाल पर शांतिभंग में कार्रवाई की जा रही है। युवती की तरफ से उसके खिलाफ कोई तहरीर नहीं दी गई है।

श्री काली मंदिर के 150 साल पुराने उर्दू-फारसी भाषा में दस्तावेज मिले, नाम था: श्री काली कोठरी

आर्यावर्त संवाददाता

मुरादाबाद। लालबाग स्थित सिद्धपीठ श्री काली मंदिर की संपत्ति से जुड़े करीब 150 वर्ष पुराने दुर्लभ दस्तावेज सामने आए हैं। तहसील और रजिस्ट्री विभाग के अभिलेखों में वर्ष 1875 के दस्तावेज मिले हैं, जो उर्दू और फारसी मिश्रित भाषा में लिखे गए हैं।

इन दस्तावेजों का अब श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा की ओर से हिंदी में अनुवाद कराया जा रहा है। अनुवाद पूरा होने के बाद मंदिर की जमीन का सीमांकन कराया जाएगा, जिससे आगे कोई नए तरीके से कब्जे का प्रयास न करे।

श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के अधीन संचालित सिद्धपीठ श्री काली मंदिर का उल्लेख पुराने दस्तावेजों में 'श्री काली कोठरी' नाम से दर्ज मिला है। अखाड़े से जुड़े संतों के अनुसार शुरुआती रिकार्ड में मंदिर की करीब छह बीघा भूमि दर्ज थी, लेकिन समय के साथ आसपास के लोगों ने बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया।

श्री काली मंदिर का जूना अखाड़ा के पास कोई स्पष्ट अभिलेख उपलब्ध नहीं था। इसके बाद अखाड़े के प्रतिनिधिमंडल ने नौ अप्रैल को महंत रह चुके सज्जन गिरी व रामगिरी को हटाने के बाद जिलाधिकारी अनुज सिंह से मुलाकात कर रिकार्ड उपलब्ध कराने की मांग की थी।

जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसील और रजिस्ट्री विभाग ने पुराने अभिलेख खोज निकाले। पुराने दस्तावेज पढ़ने में कठिनाई होने के कारण उन्हें विशेषज्ञ अनुवादक को सौंपा गया है। तहसील से गाटा संख्या भी प्राप्त हो चुकी है, जिसके आधार पर जमीन की पैमाइश कराई गई थी।

अब यह स्पष्ट किया जाएगा कि मूल रूप से कितनी भूमि दर्ज थी और वर्तमान में कितनी बची है। मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों का कहना है कि पुराने कागज मिलने से संपत्ति की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने में मदद मिलेगी। इससे भविष्य में भूमि संरक्षण और कब्जा हटाने की कार्रवाई का रास्ता भी साफ होगा। सिद्धपीठ श्री काली मंदिर में रोजाना हजारों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। नवरात्र मेले में दिल्ली, गाजियाबाद, हापुड़ समेत कई जिलों से श्रद्धालु आते हैं। वर्ष 1875 के दस्तावेज मिलना बेहद महत्वपूर्ण है। उर्दू व फारसी भाषा में मंदिर की सम्पत्ति के दस्तावेज रजिस्ट्री विभाग व तहसील से उपलब्ध हुए हैं। इनका हिंदी में अनुवाद पूरा होने के बाद मंदिर की मूल संपत्ति का पूरा रिकार्ड स्पष्ट होगा। इसके बाद सीमांकन कराया जाएगा। श्री काली मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। पुराने अभिलेख का हिंदी अनुवाद होने के बाद मंदिर की वास्तविक भूमि और इतिहास समझ आएगा। अखाड़ा मंदिर की संपत्ति सुरक्षित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। लाल बाग स्थित सिद्धपीठ श्री काली मंदिर 400 साल पुराना है। यह मंदिर टीले पर स्थित है, जिसे मिश्री गिरी का टीला भी कहा जाता है। मान्यता है कि ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेज अधिकारियों ने मंदिर की भूमि पर कब्जे का प्रयास किया था।

उस समय मठ की सेवा कर रहे मिश्री गिरी ने मंदिर परिसर की मिट्टी उठाकर फेंकी और कहा था कि जहां तक मिट्टी जाएगी, वहीं तक मठ की भूमि होगी। बताया जाता है कि मिट्टी दूर तक जाकर मिश्री में बदल गई। इस घटना के बाद अंग्रेज अधिकारियों ने कब्जे का इरादा छोड़ दिया। बाद में यहां मठ के स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और आज यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख सिद्धपीठों में गिना जाता है। सिद्धपीठ श्री काली मंदिर के पूर्व महंत सज्जन गिरी और सिद्धपीठ नौ देवी मंदिर से जुड़े रामगिरी को शिकायतों और जांच रिपोर्ट के आधार पर पद से हटाया गया था। जूना अखाड़ा को दोनों महंतों के खिलाफ करीब 150 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इनमें मंदिर संपत्ति में गड़बड़ी, प्रबंधन में अनियमितता और विवादों के आरोप शामिल थे। जूना अखाड़ा के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से भी पूरे मामले की जांच कराई थी। जांच समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद अखाड़ा ने नौ अप्रैल को कार्रवाई करते हुए दोनों महंतों को मंदिर से हटाया दिया था। इसके बाद श्री काली मंदिर में हितेश्वर गिरी महाराज को जिम्मेदारी सौंपी गई। जूना अखाड़ा ने अब नई व्यवस्था लागू की है। जूना अखाड़ा की नई व्यवस्था के तहत श्री काली मंदिर, सिद्धपीठ नौ देवी मंदिर और रामगंगा मंदिर में स्थायी महंत नियुक्त नहीं किए गए हैं। अखाड़ा ने निर्णय लिया था कि आठ-आठ दिन बाद तीनों मंदिरों में महंतों का स्थानांतरण किया जाएगा, ताकि मंदिर संपत्तियों और प्रबंधन में पारदर्शिता बनी रहे।

दुर्गा धाम देवनगर में गूंजेगी रामकथा, जुटेंगे हजारों रामभक्त

अखंडनगर/सुल्तानपुर। जनपद सुल्तानपुर के पूर्वी छोर स्थित दुर्गा धाम देवनगर में पांच दिवसीय भव्य रामकथा का आयोजन किया जा रहा है। कन्हाइन समिति खानपुर पिलाई कोट के सौजन्य से आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में क्षेत्र भर के रामभक्तों के जुटने की संभावना है।

यह रामकथा 29 मई से प्रारम्भ होकर 2 जून तक चलेगी। कथा वाचन के लिए अयोध्या धाम से पधार रहीं प्रसिद्ध कथावाचिका देवी सुनैना कृष्णा जी श्रद्धालुओं को प्रभु श्रीराम की दिव्य कथा का रसपान कराएंगी। समिति के पदाधिकारियों के अनुसार, यह आयोजन कछवाहा वंशी क्षत्रियों एवं रक्त संबंधियों की कुल देवी जमवाय माता मंदिर परिसर में किया जा रहा है। कार्यक्रम में सुल्तानपुर के साथ-साथ अंबेडकरनगर, आजमगढ़ और जौनपुर जनपदों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है।

मऊ से मुख्यमंत्री की माफिया को दो टूक चेतावनी, कहा- त्योहारों में व्यवधान डालने वालों की होगी रावण-कंस जैसी दुर्गति

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मऊ की धरती से माफिया, गुंडों और अराजक तत्वों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अब किसी में इतना दुस्साहस नहीं बचा है कि धार्मिक आयोजनों या त्योहारों में व्यवधान डाल सके। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि किसी ने रामलीला, यज्ञ-कथा, जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि, रक्षाबंधन जैसे धार्मिक आयोजनों में बाधा डालने का प्रयास किया, तो उसकी दुर्गति रावण और कंस जैसी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बेटी और व्यापारी की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों का इंतजार अब केवल यमराज करेंगे।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को मऊ के गांधी मैदान में 392 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 114 विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मऊ को क्रांतिधरा बताते हुए साहित्यकार श्याम नारायण पांडेय, समाज सुधारक स्वामी सहजानंद सरस्वती, पूर्व केंद्रीय मंत्री कल्पनाथ राय, पूर्व राज्यपाल फागू चौहान तथा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को नमन किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अच्छी सरकार विकास लेकर आती है और विकास किसी जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करता। सड़क, पुल, स्वास्थ्य केंद्र और बाढ़ सुरक्षा परियोजनाएं सभी नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का माध्यम बनती हैं। उन्होंने कहा कि जब अच्छे लोग चुने जाते हैं तो अच्छी सरकार बनती है, लेकिन गलत लोगों के चयन से सुरक्षा में सेंध लगती है, विकास का धन लूट का शिकार होता है और बेटियों तथा व्यापारियों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है।योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय धार्मिक आयोजनों में व्यवधान डाला जाता था और माफिया का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 में भरत-मिलाप कार्यक्रम के दौरान मऊ में दंगा कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। सत्ता संरक्षण में माफिया रामलीला जैसे आयोजनों में बाधा डालते थे और निर्दोष लोगों की जान जाती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय सरकारें माफिया के सामने नतमस्तक थीं और प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई थी।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में व्यापक परिवर्तन देखा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब, युवा, महिला और किसान को विकास की चार सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं और इन्हीं वर्गों के उत्थान से देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2014 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं को लागू नहीं होने दिया।योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज प्रदेश में 65 लाख गरीबों को आवास, करोड़ों परिवारों को शौचालय और करोड़ों लोगों को निःशुल्क राशन की सुविधा मिल रही है। आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जनआरोग्य योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि किसान परिवारों को संकट की घड़ी में त्वरित आर्थिक सहायता दी जा रही है।मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास का अभियान बिना रुके, बिना झुके और बिना थके जारी है। सड़क, पुल, बिजली, पेयजल, पर्यटन, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है।

चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री ने अर्पित की श्रद्धांजलि, किसानों के हितों को बताया विकास का आधार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को विधान भवन परिसर में स्थापित उनकी प्रतिमा के सम्मुख चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चौधरी चरण सिंह के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का स्मरण करते हुए उन्हें किसानों का सच्चा मसीहा तथा भारत माता का महान सपूत बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की पावन पुण्यतिथि है। उन्होंने कहा कि 29 मई, 1987 को चौधरी चरण सिंह अपनी नश्वर काया का त्याग कर दिवंगत हुए थे, लेकिन किसानों, गांवों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की उनकी सोच आज भी देश और समाज के लिए प्रेरणास्रोत बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 23 दिसम्बर, 1902 को उत्तर प्रदेश की धरती पर जन्मे चौधरी चरण सिंह ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए देश के लिए अमूल्य योगदान दिया था।योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने कृषि और राजस्व क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए, जिसका लाभ देश के किसानों को लंबे समय तक मिला। उनका स्पष्ट मत था कि देश के विकास का रास्ता गांवों और खेत-खलिहानों से होकर जाता है। इसलिए किसान केवल विकास की प्रक्रिया का हिस्सा ही नहीं, बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं के केंद्र में होने चाहिए। शासन की योजनाएं किसानों की आवश्यकताओं और हितों को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए, ताकि ग्रामीण भारत आत्मनिर्भर और समृद्ध बन सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि देशहित और किसान कल्याण के लिए चौधरी चरण सिंह द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार चौधरी चरण सिंह की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने और किसानों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। इसी क्रम में लखनऊ में प्रस्तावित चौधरी चरण सिंह सीड पार्क एक महत्वपूर्ण पहल है, जो कृषि क्षेत्र में नवाचार और किसानों की प्रगति के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को मिली बड़ी मजबूती, उप मुख्यमंत्री ने 192 .15 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का विस्तार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत संचालित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल 192 करोड़ 15 लाख रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह निर्णय प्रदेश में लघु खाद्य उद्योगों को नई गति देने के साथ-साथ स्थानीय उद्यमिता को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।उप मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत धनराशि का वितरण विभिन्न अनुदान मदों के अंतर्गत पारदर्शी एवं वर्गवार तरीके से सुनिश्चित किया गया है। स्वीकृत बजट में अनुदान संख्या-10 के अंतर्गत 167 करोड़ 55 लाख रुपये, अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत 2 करोड़ 52 लाख रुपये तथा अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत 22 करोड़ 8 लाख रुपये सम्मिलित हैं। इस प्रकार कुल 192 करोड़ 15 लाख रुपये की राशि योजना के प्रभावी संचालन और लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाने के लिए स्वीकृत की गई है।केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि यह योजना विशेष रूप से सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के उन लाभार्थियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी, जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नया उद्यम स्थापित करना चाहते हैं अथवा अपने वर्तमान व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं। सरकार की यह पहल स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगी।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत जारी की गई यह धनराशि स्थानीय उत्पादकों, स्वयं सहायता समूहों और छोटे उद्यमियों को 'स्थानीय के लिए स्वर' तथा 'आत्मनिर्भर भारत' की अवधारणा को मजबूत करने में सहायता देगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वीकृत अनुदान की राशि बिना किसी बाधा और पूरी पारदर्शिता के साथ सीधे पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे, जिससे योजना का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित हो सके।उन्होंने कहा कि इस धनराशि का उपयोग सूक्ष्म खाद्य इकाइयों के आधुनिकीकरण, तकनीकी सहयोग, कौशल प्रशिक्षण, उन्नत पैकेजिंग तथा विपणन सहायता उपलब्ध कराने में किया जाएगा। इससे कृषि उत्पादों की बर्बादी को कम करने में मदद मिलेगी, किसानों की आय में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा तथा स्थानीय स्तर पर व्यापक रोजगार सृजन को बल मिलेगा।उप मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग गुणवत्ता, पारदर्शिता और निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए, ताकि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लक्ष्यों को समय से प्राप्त कर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को नई ऊंचाई दी जा सके।

• संक्षेप •

गोमतीनगर में छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली, पुलिस ने शुरू की गहन जांच

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर क्षेत्र स्थित सृजन विहार कॉलोनी में एक 16 वर्षीय छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही थाना गोमतीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए फॉरेंसिक टीम की मदद से आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार 28 और 29 मई 2026 की मध्य रात्रि करीब 12 :30 बजे आगंतुक रितेश रंजन चौबे द्वारा थाना गोमतीनगर में सूचना दी गई कि उनके चालक अभिषेक सक्सेना की पुत्री पारुल, जो गोमतीनगर क्षेत्र स्थित सृजन विहार कॉलोनी में रहकर अध्ययन कर रही थी, मृत पाई गई है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटानी शुरू की।जांच के दौरान पुलिस ने संबंधित आवास पर मौजूद लोगों से पूछताछ की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार छात्रा अध्ययन के उद्देश्य से वहां रह रही थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों को भी सूचित किया गया और मृतका के पिता से बातचीत की गई।मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल फॉरेंसिक दल को मौके पर बुलाकर आवश्यक साक्ष्य संकलित किए। इसके बाद वैधानिक प्रक्रिया पूरी करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े सभी तथ्यों और परिस्थितियों की गहनता से जांच की जा रही है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना के कारणों को लेकर स्पष्ट स्थिति सामने आ सकेगी।

दारूलसफा के पास युवक को मारी गोली, एक आरोपी हिरासत में, दूसरे की तलाश में दबिश जारी

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में देर रात गोली चलने की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। दारूलसफा के पास स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स के निकट एक युवक को गोली मार दिए जाने की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही थाना हजरतगंज पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मामले में दो नामजद आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है।पुलिस के अनुसार 28 और 29 मई 2026 की मध्य रात्रि लगभग एक बजे सूचना प्राप्त हुई कि दारूलसफा के पास बने सुलभ कॉम्प्लेक्स के निकट एक व्यक्ति को गोली लगी है। सूचना मिलते ही थाना हजरतगंज पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल युवक को प्राथमिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया। चिकित्सकों द्वारा स्थिति को देखते हुए उसे आगे के उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया।घायल की पहचान विभू शुक्ला पुत्र स्वर्गीय राकेश कुमार शुक्ल निवासी नरही, थाना हजरतगंज के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक युवक के दाहिने पैर की जांघ में गोली लगी है। वर्तमान में उसका उपचार जारी है और चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।घटना के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हजरतगंज में मोहम्मद शफीक और मोहम्मद वाजिद के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोहम्मद शफीक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं घटना में वांछित दूसरे आरोपी वाजिद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना से जुड़े सभी पहलुओं और परिस्थितियों की गहन जांच की जा रही है। घटनास्थल के आसपास के साक्ष्यों को एकत्र किया जा रहा है तथा अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई भी प्रचलित है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही फरार आरोपी को गिरफ्तार कर घटना के कारणों का खुलासा किया जाएगा।

बीबीएयू में 'विवेकानंद मार्ग' पर मंथन, आधुनिक भारत के लिए व्यावहारिक अध्यात्म को बताया जरूरी

लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में शुक्रवार को 'लिविंग द विवेकानंद वे : प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी फॉर मॉडर्न इंडिया' पुस्तक पर संवादात्मक चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें आधुनिक भारत में स्वामी विवेकानंद के विचारों की प्रासंगिकता, व्यावहारिक अध्यात्म, युवा सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर विस्तृत मंथन हुआ। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए केवल आर्थिक उन्नति ही नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों, सामाजिक समरसता, आध्यात्मिक चेतना और युवा शक्ति के सकारात्मक उपयोग को भी प्राथमिकता देनी होगी।कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने की। पुस्तक का सह–लेखन अनुवाद सॉल्यूशंस की निदेशक डॉ. अनन्या अवस्थी और विवेकानंद केंद्र, उत्तर प्रांत के उपप्रमुख डॉ. निखिल यादव द्वारा किया गया है, जो कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मंच पर प्रसिद्ध लोकगायिका एवं समाजसेवी मालिनी अवस्थी, शिक्षा विभाग के कार्यवाहक विभागाध्यक्ष डॉ. हरिशंकर सिंह तथा कार्यक्रम संयोजक डॉ. सुभाष मिश्रा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। इसके पश्चात विश्वविद्यालय कुलगीत का गायन किया गया तथा अतिथियों को पुष्पगुच्छ, स्मृति चिह्न एवं शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया।कार्यक्रम संयोजक डॉ. सुभाष मिश्रा ने उपस्थित अतिथियों, शिक्षकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा और उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह संवाद नई पीढ़ी को स्वामी विवेकानंद के विचारों को वर्तमान सामाजिक और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समझने का अवसर प्रदान करेगा। अपने अध्यक्षीय संबोधन में कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने पुस्तक और युवा लेखकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं को स्वामी विवेकानंद और डॉ. भीमराव अम्बेडकर जैसे महान व्यक्तित्वों के जीवन, विचार और संघर्ष को गहराई से समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब दुनिया भारत को केवल 'सांप–सपेरों का देश' कहकर देखती थी, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने अपने ज्ञान, विचार और आध्यात्मिक चेतना के बल पर विश्व मंच पर भारत की नई पहचान स्थापित की।प्रो. मित्तल ने कहा कि आज विश्व भारत की ओर आशा और विश्वास से देख रहा है।

बिजली कर्मियों के तबादले 15 जुलाई तक बढ़ाने का प्रस्ताव

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। प्रदेश में भीषण गर्मी और लगातार बढ़ती बिजली मांग के बीच उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के उद्देश्य से अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। कारपोरेशन ने वार्षिक स्थानांतरण नीति 2026-27 के अंतर्गत तबादलों की अंतिम तिथि को 31 मई से बढ़ाकर 15 जुलाई 2026 तक करने का अनुरोध किया है, ताकि वर्तमान परिस्थितियों में बिजली व्यवस्था प्रभावित न हो और उपभोक्ताओं को सुचारु आपूर्ति मिलती रहे।उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नितीश कुमार द्वारा 26 मई 2026 को विशेष सचिव, ऊर्जा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि शासन की वार्षिक स्थानांतरण नीति के अनुसार सभी विभागीय स्थानांतरण 31 मई 2026 तक पूर्ण किए जाने हैं। हालांकि वर्तमान में प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु के कारण प्रचंड गर्मी और हीटवेव की स्थिति बनी हुई है, जिससे बिजली की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की जा रही है।पत्र में उल्लेख किया गया है कि बढ़ी हुई मांग के चलते विद्युत लाइनों और उपकरणों के अनुरक्षण के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त निगरानी और त्वरित समस्या समाधान की आवश्यकता पड़ रही है। ऐसी परिस्थितियों में पहले से क्षेत्रों में तैनात और स्थानीय परिस्थितियों से परिचित अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवाएं अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। कारपोरेशन ने कहा है कि यदि वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किए जाते हैं, तो विद्युत आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

पारा में पारिवारिक विवाद ने लिया कानूनी रूप, महिला उपनिरीक्षक समेत दोनों पक्षों ने दर्ज कराए मुकदमे

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद का मामला गंभीर आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया है। मामले में दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिए गए हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने अलग-अलग धाराओं में मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि प्रकरण की निष्पक्ष एवं गहन विवेचना की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।पुलिस के अनुसार विवाद उस समय और गंभीर हो गया जब वर्तमान में प्रयागराज जनपद में महिला उपनिरीक्षक के पद पर तैनात महिला ने अपने पति, सास-ससुर और अन्य ससुरालीजनों पर गंभीर आरोप लगाए। महिला ने मारपीट, दहेज उत्पीड़न, दुष्कर्म, विष देकर नुकसान पहुंचाने तथा जान से मारने के प्रयास जैसे आरोप लगाते हुए थाना पारा में शिकायत दर्ज कराई।

मोहनलालगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 89 मुकदमों में जब्त 4200 लीटर अवैध शराब नष्ट

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वर्ष 2017 से 2025 के बीच विभिन्न मामलों में बरामद और जब्त की गई लगभग 4200 लीटर अवैध कच्ची एवं देशी शराब को नियमानुसार नष्ट करा दिया। न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की गई इस कार्रवाई को पुलिस प्रशासन ने अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और तस्करी के विरुद्ध चल रहे अभियान में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।पुलिस आयुक्त अमरेन्द्र सिंह सेंगर के निर्देशानुसार जनपद में लंबित मालों के निस्तारण के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में यह कार्रवाई मोहनलालगंज थाना पुलिस द्वारा संपादित की गई। पुलिस उपायुक्त दक्षिणी अमित कुमार आनन्द के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी रल्लापल्ली बसंथ कुमार तथा सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज ज्ञानेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना पुलिस ने इस प्रक्रिया को पूरा कराया।पुलिस के अनुसार मा. न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में थाना मोहनलालगंज पर वर्ष 2017 से वर्ष 2025 के मध्य पंजीकृत कुल 89 अभियोगों में बरामद की गई अवैध शराब को नष्ट किया गया। कार्रवाई के दौरान थाना परिसर में जेसीबी मशीन की सहायता से गड्ढा खुदवाकर लगभग 4200 लीटर कच्ची और देशी शराब को पूरी तरह नष्ट कराया गया।पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूरी प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा, पारदर्शिता और विधिक मानकों का विशेष ध्यान रखा गया। शराब नष्ट करने की कार्रवाई सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं का पालन करते हुए की गई।

पुस्तक चर्चा- 'संजय उवाच' -वैचारिक पुनर्जागरण का जीवंत आख्यान

समीक्षक-डा. रजनीश अग्रहरि

पुस्तकः संजय उवाच (प्रो.संजय द्विवेदी के व्याख्यान)

प्रकाशकः शिल्पायन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स,

10295, लेन नंबर-1,वैस्ट गोरखपार्क, शाहदरा, दिल्ली-110032

मूल्यः 495 (पेपरबैक), पृष्ठ-370

समकालीन भारतीय बौद्धिक परिदृश्य में ऐसी पुस्तकें विरल हैं, जो एक साथ पत्रकारिता, संस्कृति, भाषा, शिक्षा, लोकतंत्र और भारतीय चिंतन की बहुआयामी यात्रा का विश्वसनीय दस्तावेज बन सकें। प्रो. संजय द्विवेदी का शिल्पायन से सद्यः प्रकाशित व्याख्यान संग्रह 'संजय उवाच' केवल उनके व्याख्यानों का संकलन नहीं, अपितु भारतीय मन, मीडिया और समाज के अंतर्द्वंद्वों का वैचारिक मानचित्र है। 45 अध्यायों में विस्तृत यह कृति वर्तमान समय के बौद्धिक संकटों के बीच भारतीय दृष्टि की पुनर्स्थापना का सशक्त प्रयास करती है। पुस्तक के शीर्षक से ही स्पष्ट हो जाता है कि लेखक केवल वक्ता नहीं, बल्कि एक ऐसे चिंतक हैं जो संवाद को समाज परिवर्तन का माध्यम मानते हैं। पुस्तक की भूमिका में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने ठीक ही लिखा है कि-"संजय उवाच को पढ़ना मानो विचारों की भारत यात्रा में शामिल होना है।"

पुस्तक का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य इसका संवादधर्मी स्वर है। लेखक उपदेशक की मुद्रा में नहीं, बल्कि एक सहयात्री चिंतक के रूप में पाठक से संवाद करता है। प्राक्कथन 'मन की बात' में उल्लिखित 'वाक शक्ति' की अवधारणा पुस्तक की आत्मा है। प्रो. द्विवेदी संवाद को केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि सभ्यता की प्राणशक्ति मानते हैं। उनके अनुसार संवाद ही वह शक्ति है, जो समाज को विभाजन से विमर्श और अंधकार से बौद्धिक आलोक की ओर ले जाती है। यही कारण है कि पुस्तक का प्रथम अध्याय 'संवाद से बनेगी सुंदर दुनिया' केवल प्रेरक लेख नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक सहअस्तित्व का सांस्कृतिक घोषणापत्र प्रतीत होता है। मीडिया विमर्श पर लेखक की दृष्टि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ऐसे समय में जब पत्रकारिता बाजारवाद, तात्कालिकता और वैचारिक ध्रुवीकरण के दबावों से जूझ रही है, लेखक मीडिया को पुनः 'सरोकार' से जोड़ने का आग्रह करता है। वे स्पष्ट करते हैं कि पत्रकारिता महज सूचना उद्योग नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना का नैतिक दायित्व है। 'जड़ों की ओर लौटे मीडिया' जैसे अध्यायों में भारतीय लोकजीवन, मानवीय संवेदना और सामाजिक प्रतिबद्धता को मीडिया का मूल आधार बताया गया है। ओड़िया संत-कवि भीम भोई की करुणा-दृष्टि को उद्धृत करते हुए लेखक मीडिया को जनकल्याण और राष्ट्र-निर्माण का माध्यम बनाने की प्रेरणा देता है।

इसी प्रकार पुस्तक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष मीडिया शिक्षा और डिजिटल युग पर उसका गंभीर चिंतन है। प्रो. द्विवेदी भारतीय मीडिया शिक्षा के औपनिवेशिक ढाँचे पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं। वे पूछते हैं कि भारतीय मीडिया संस्थानों में भारतीय संदर्भ, भारतीय भाषाएँ और भारतीय अनुभव अभी भी हाशिए पर क्यों हैं। यह प्रश्न केवल शिक्षा का नहीं, बल्कि बौद्धिक आत्मनिर्भरता का प्रश्न है। लेखक नवाचार, री-स्किलिंग और मीडिया साक्षरता को डिजिटल युग की अनिवार्य शर्त मानते हैं। 'फेक न्यूज' और सूचना-अराजकता के इस दौर में उनका यह आग्रह अत्यंत प्रासंगिक प्रतीत होता है कि मीडिया साक्षरता को सामाजिक आंदोलन का रूप दिया जाना चाहिए। समकालीन भाषायी विमर्श के सन्दर्भ में लेखक की दृष्टि विशेष रूप से संवेदनशील और भारतीयता से अनुप्राणित है साथ ही भाषा और सांस्कृतिक अस्मिता पर वह अंग्रेजी के वर्चस्व को भारतीय भाषायी संवाद के लिए एक गंभीर चुनौती मानते हैं साथ ही हिंदी को भारतीय एकता की स्वाभाविक सेतु-भाषा के रूप में स्थापित करते हैं। किंतु उनका हिंदी-विमर्श किसी भाषाई वर्चस्व का आग्रह नहीं, बल्कि भारतीय भाषाओं के सामूहिक सम्मान का पक्षधर है। 'भाषा है सिनेमा की शक्ति' अध्याय में हिंदी सिनेमा की वैश्विक स्वीकार्यता को भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव और 'सॉफ्ट पावर' के रूप में देखा गया है। राज कपूर से लेकर लोकभाषाओं तक लेखक ने भाषा को केवल संप्रेषण नहीं, बल्कि सांस्कृतिक स्मृति और राष्ट्रीय अस्मिता का वाहक माना है। पुस्तक का वैचारिक विस्तार इसे और अधिक महत्त्वपूर्ण बनाता है। डॉ. भीमराव अंबेडकर, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और तुलसीदास जैसे व्यक्तित्वों पर लेखक का चिंतन भारतीय समाज के विविध आयामों को समेटता है। 'सबके हैं – सबमें हैं तुलसी के राम' तथा 'मुसलमान, हिंदू और हिन्दुस्तानियत' जैसे अध्याय सामाजिक समरसता और साझा सांस्कृतिक विरासत के प्रश्नों को अत्यंत संतुलित और मानवीय दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं। लेखक भारत को मात्र राजनीतिक राष्ट्र-राज्य नहीं, बल्कि करुणा, सहअस्तित्व और सांस्कृतिक निरंतरता से निर्मित एक जीवंत सभ्यता के रूप में देखते हैं। नई शिक्षा नीति, सुशासन और आत्मनिर्भर भारत पर पुस्तक के विचार भी अत्यंत सार्थक हैं। लेखक 'गवर्नमेंट' से आगे बढ़कर 'गवर्नेंस' की अवधारणा को जनसंवाद और लोकभागीदारी से जोड़ते हैं। शिक्षा के संदर्भ में वे रटंत व्यवस्था से मुक्त होकर तार्किकता, सृजनात्मकता और भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित शिक्षा की आवश्यकता पर बल देते हैं। उनका विश्वास है कि भारत का भविष्य केवल तकनीकी दक्षता में नहीं, बल्कि सांस्कृतिक आत्मविश्वास और बौद्धिक स्वाधीनता में निहित है। शैली की दृष्टि से भी 'संजय उवाच' उल्लेखनीय कृति है। प्रो. संजय द्विवेदी की भाषा सहज, प्रवाहपूर्ण और वैचारिक गरिमा से संपन्न है। उनकी लेखनी में पत्रकार की तथ्यपरकता, शिक्षक की स्पष्टता और चिंतक की गहराई एक साथ उपस्थित दिखाई देती है। कहीं भी अनावश्यक बौद्धिक जटिलता नहीं है, फिर भी विचारों की गंभीरता पाठक को लगातार आत्ममंथन के लिए प्रेरित करती है। उनकी भाषा में भारतीय संवेदना का वह आलोक है, जो वैदिक चेतना और आधुनिक विवेक के सुंदर समन्वय के रूप में उभरता है। समग्रतः, 'संजय उवाच' हमारे समय के वैचारिक और सांस्कृतिक संकटों के बीच भारतीय दृष्टि की पुनर्प्रतिष्ठा का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह पुस्तक केवल मीडिया या संचार के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस गंभीर पाठक के लिए आवश्यक है जो भारत, भारतीयता, लोकतंत्र, भाषा और सांस्कृतिक चेतना के अंतर्संबंधों को गहराई से समझना चाहता है। यह कृति अंततः हमें यही स्मरण कराती है कि सभ्यता का वास्तविक आधार शक्ति नहीं, बल्कि संवाद है; और संवाद तभी सार्थक होता है, जब उसमें सत्य, संवेदना और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का भाव उपस्थित हो।

(समीक्षक हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय, सागर में उपाचार्य हैं।)

'कॉकरोच जनता पार्टी' की डिजिटल लोकप्रियता के सियासी निहितार्थ

कॉकरोच जनता पार्टी जैसे व्यंग्यात्मक डिजिटल पेज को लाखों लाइक मिलना केवल इंटरनेट-मज़ाक नहीं माना जा सकता, बल्कि यह कई गहरे सामाजिक-राजनीतिक संकेत देता है- खासकर युवाओं, मध्यम वर्ग और डिजिटल समाज की मानसिकता के बारे में। यही वजह है कि केंद्र-राज्यों में सत्तारूढ़ दलों और नागरिक प्रशासन को सावधान हो जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें अगली जेन-जी क्रांति के साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। बताया जाता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की टिप्पणी अशोभनीय थी, जिससे अब खुद भी वो मुकर चुके हैं, लेकिन उनकी उक्ति ने सत्ता प्रतिष्ठान की सोच को उजागर करके लोगों को भड़काने का काम किया है, और शायद विपक्षी दलों के हिमायती लोग और उनकी समर्थक युवा पीढ़ी इसी मौके की तलाश में थी, जो कॉकरोच जनता पार्टी जैसे व्यंग्यात्मक डिजिटल पेज के सृजन और उसको मिले लाखों लाइक से स्पष्ट होती है। इसे केवल इंटरनेट-मज़ाक समझने की बजाए इस असंतोष की जड़ में जाना होगा।

कॉकरोच जनता पार्टी' की डिजिटल लोकप्रियता के सियासी निहितार्थ निम्नलिखित हैः-

पहला, व्यवस्था के प्रति बढ़ती निराशा-हताशाः जब बड़ी संख्या में लोग किसी व्यंग्यात्मक या मीम-आधारित राजनीतिक पेज से जुड़ते हैं, तो इसका अर्थ होता है किः लोग पारंपरिक राजनीति से असंतुष्ट हैं, और उन्हें लगता है कि उनकी समस्याएँ नहीं सुनी जा रहीं, और वे गुस्से को हास्य, व्यंग्य और डिजिटल ट्रेंड के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। दूसरा, जेन-जी (Gen-Z) की "डिजिटल राजनीति": आज की युवा पीढ़ी सड़क से पहले सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देती है, मीम, रील, ट्रोलिंग और व्यंग्य को राजनीतिक अभिव्यक्ति का माध्यम बना चुकी है। इसलिए ऐसे पेज "डिजिटल जनमत" का संकेत बन जाते हैं।

तीसरा, बेरोज़गारी और अवसर संकट का दबावः ऐसे प्लेटफॉर्मों की लोकप्रियता अक्सर इन मुद्दों से जुड़ती हैः बेरोज़गारी, परीक्षा पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में देरी, महंगाई, और अवसरों में असमानता। लिहाजा, जब युवाओं को लगता है कि मेहनत के बावजूद व्यवस्था निष्पक्ष नहीं है, तब व्यंग्यात्मक आंदोलन लोकप्रिय होने लगते हैं।

चौथा, राजनीतिक दलों पर भरोसे में गिरावटः यह संकेत भी माना जा सकता है कि कुछ युवाओं को मुख्यधारा के दलों में अपना प्रतिनिधित्व नहीं दिख रहा, वे "एंटी-एस्टैब्लिशमेंट" भावनाओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यानी वे सीधे किसी पार्टी का समर्थन नहीं, बल्कि "सिस्टम विरोधी भावना" व्यक्त कर रहे हैं।

पांचवां, डिजिटल असंतोष भविष्य में वास्तविक आंदोलन बन सकता हैः इतिहास बताता है कि कई बड़े आंदोलन पहले सोशल मीडिया ट्रेंड के रूप में शुरू हुए, और बाद में वे वास्तविक राजनीतिक दबाव में बदल गए। हालाँकि हर वायरल ट्रेंड आंदोलन नहीं बनता, लेकिन यह "सामाजिक तापमान" अवश्य दिखाता है।

छठा, हास्य अब राजनीतिक हथियार बन चुका हैः पहले राजनीतिक विरोध भाषण, धरना, पोस्टर तक सीमित था। अब मीम, पैरोडी, व्यंग्यात्मक नाम, वायरल वीडियो भी जनभावना को प्रभावित कर रहे हैं।

सातवां, भारत में "डिजिटल क्रांति" का संकेतः यह भी माना जा सकता है कि भारत में असंतोष फिलहाल संगठित सड़क आंदोलन से ज्यादा, डिजिटल संस्कृति में दिखाई दे रहा है। यानी भारत का जेन-जेड (Gen-Z) पहले "ऑनलाइन राजनीतिक चेतना" बना रहा है। लेकिन सावधानी भी जरूरी सोशल मीडिया की लोकप्रियता हमेशा वास्तविक जनसमर्थन के बराबर नहीं होती।

जानकारों की मानें तो कई बार एल्गोरिद्म, ट्रेंडिंग संस्कृति, मनोरंजन, और क्षणिक गुस्सा भी किसी पेज को वायरल बना देते हैं। इसलिए इसे पूर्ण राजनीतिक क्रांति का संकेत मानना जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसे युवाओं की बेचैनी और व्यवस्था से असंतोष का महत्वपूर्ण डिजिटल संकेत जरूर माना जा सकता है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ठीक ही कहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी कोई मान्यता दल नहीं है, न ही उसकी कोई घोषित नीति-सिद्धांत है। फिर भी पेज की लोकप्रियता विपक्षी नेताओं के मनोबल बढ़ाने को काफी हैं।

मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार और नितिन नवीन की कार्यकारणी इसी पखवाड़े में , सुनील बंसल होगें संगठन महा सचिव

उत्तर प्रदेश से जगदंबिका पॉल, बिहार से वकील साहब रविशंकर प्रसाद और राजीव प्रताप रूडी, शामिल है।

अजय दीक्षित

लुटियंस पर पकड़ रखने वाले सूत्र ने बताया है कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार इसी हफ्ते दस दिन में हो सकता है, सूत्रों की माने तो कम से कम आठ मंत्री हटाए जा सकते हैं जिसमें सबसे बड़े नाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पेट्रोलियम मंत्री हरदेव पूरी शामिल है।जिन चेहरों को जगह मिल सकती है उनमें कर्नाटक से सूर्या, हिमाचल से अनुराग ठाकुर, पंजाब से राघव चड्ढा और क्रिकेट खिलाड़ी हरभजन सिंह शामिल हैं। यह विस्तार उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, कर्नाटक, गोवा, विधानसभा चुनाव को लेकर किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश से जगदंबिका पॉल, बिहार से वकील साहब रविशंकर प्रसाद और राजीव प्रताप रूडी, शामिल है। उत्तर प्रदेश से कानपुर के संसद रमेश अवस्थी , देवरिया से संसद प्रेम मणि त्रिपाठी को शामिल किया जा सकता है वही एल मुरुगन, भूपति राजू को मंत्रिमंडल से हटाकर संगठन में भेजा जा सकता है। नितिन नवीन की कार्यकारणी में 08 महासचिव,08 उपाध्यक्ष, एक एक राज्यों से होगें, सांसद, विधायक को संगठन के पद नहीं मिल सकेंगे।

मोदी मंत्रिमंडल का 2024 के बाद पहला विस्तार है ।एनडीए के सहयोगियों को भी जगह मिल सकती है बिहार से संजय कुमार झा, मंत्री परिषद में आ सकते हैं।

नितिन नवीन की कार्यकारणी भी इसी 10 में जाएगी क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह यानी महासचिव दत्तात्रेय होसबोल जी से भी संगठन मंत्रियों को लेकर चर्चा हुई है। नितिन नवीन की कार्यकारणी में पचास वर्ष तक के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 46 वर्ष के है । समझा जाता है कि राष्ट्रीय महासचिव संगठन बी एल संतोष अवकाश ग्रहण करेंगे उनके स्थान पर पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में महती भूमिका निभा चुके महासचिव सुनील बंसल अब संगठन महा सचिव होंगे,क्षेत्रीय प्रचारक शिवप्रकाश,अजय जंबाल संघ में बापिस जायेंगे।

सबसे उलझा हुआ काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आए वरिष्ठ प्रचारकों को समावेश करना है।यह कार्य दत्तात्रेय होसबोल को करना है।सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रांत प्रचारक स्तर के और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाग प्रचारक स्तर को संघ ने तय किया। केंद्रीय कार्यालय प्रमुख महासचिव अरुण सिंह के स्थान पर सौदान सिंह, और गणेश मिश्रा के किसी राज्य के संगठन महा मंत्री पद की आने की संभावना। गणेश मिश्रा अभी बंगाल में क्षेत्रीय प्रचारक हो कर मजदूर संघ के काम को देख रहे हैं।

संघ की ओर से भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य संगठन में समन्वय का काम अखिल भारतीय स्तर पर सदस्य अरुण जैन, और सुरेश सोनी को तय करना है।

केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में नए राज्य महासचिव संगठन तैनात किये जायेंगे जो इन्हीं राज्यों के होंगे। हिंदी भाषी राज्यों में नितिन नवीन संघ से क्षेत्रीय प्रचारक स्तर के लोग मांगे हैं। दत्तात्रेय होसबोल जी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत जी से सैद्धांतिक सहमति ली है।मोदी मंत्रिमंडल में सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों,जातियों,उपजातियों, अनुसूचित जाति, जनजाति,वर्गों, भाषाई आधार, समावेश किया जाएगा। लेकिन प्राथमिकता तोर पर युवाओं को मौका दिया जाने के संकेत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी, योगी आदित्यनाथ, हेमंत विश्व शर्मा, मोहन यादव, नायब सिंह सैनी,में से दो को भाजपा की सर्वोच्च संस्था केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड में सदस्य बनाया जा सकता है।अभी ये लोग मुख्यमंत्री के नाते बोर्ड के सदस्य थे।कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। जिनमें भूपेंद्र सिंह, इन्द्रजीत सिंह, शामिल हैं।

राष्ट्रपति श्री मति द्रोपदी मुर्मू के कार्यकाल समाप्ति के बाद नए चुनाव के उम्मीदवार भी दिल्ली के सत्ता गलियारों में घूमने लगा है। सूत्रों ने जिन नामों की चर्चा की है उनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम भी है। भारतीय जनता पार्टी में निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है। यह कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर संघ तक जाता है।

टिप्पणी

टीएमसी की उम्मीद गलत साबित हुई

टीएमसी की ये उम्मीद गलत साबित हुई कि बांग्ला अस्मिता की प्रतिनिधि के रूप में खुद पेश कर वह 'हिंदुत्व- हिंदी' पहचान वाली भाजपा को जीतने से रोक देगी। असम में ऐसी सोच पहले ही गलत साबित हो चुकी है।

पश्चिम बंगाल का सियासी किला फतह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2026 का विधानसभा चुनाव युद्ध के अंदाज में लड़ा। अपने पास मौजूद तमाम गोले तो उसने वहां दागे ही, केंद्र में सत्ताधारी होने के नाते शासन तंत्र से हासिल होने वाली ताकत एवं प्रभाव का भी बेहिचक उपयोग किया। अपनी खास जूझारू भावना के लिए चर्चित ममता बनर्जी को चारों तरफ से घेर लेने की ये रणनीति कामयाब रही है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की विवादास्पद प्रक्रिया से तृणमूल कांग्रेस के लिए मुकाबले का धरातल असमान हो जाने के संकेत लगातार मिल रहे थे।

निर्वाचन आयोग के अन्य कदमों ने टीएमसी की राह को और भी कठिन बनाया। अन्य संवैधानिक संस्थाओं ने भी चुनाव प्रक्रिया पर उठे प्रश्नों की फिक्र नहीं की। 15 साल लगातार सत्ता में रहने के बाद किसी नेता या पार्टी के लिए चुनावी मुकाबला वैसे भी आसान नहीं रह जाता। एंटी-इन्कबेंसी से उत्पन्न चुनौतियां उसके सामने खड़ी होती हैं। ये सारे पहलू मिलकर इस बार ममता बनर्जी पर भारी पड़े। टीएमसी की ये उम्मीद कमजोर जमीन पर खड़ी नजर आई कि बांग्ला अस्मिता की प्रतिनिधि के रूप में खुद पेश कर वह 'हिंदुत्व- हिंदी' पहचान वाली भाजपा को जीतने से रोक देगी। असम में ऐसी सोच एक दशक पहले ही गलत साबित हो चुकी थी। अब वहां भाजपा ने जीत की हैट-ट्रिक बनाई है। इस बार वह और बड़े बहुमत से सत्ता में लौट रही है।

यह इस समझ की पुष्टि है कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा के नेतृत्व में उग्र हिंदुत्व और कैश ट्रांसफर के जरिए मतदाताओं को लुभाने की रणनीति वहां कामयाब बनी हुई है। इसके अलावा संभव है राज्य में हुए विवादास्पद परिसीमन का लाभ भी भाजपा को मिला हो। वैसे, इन बातों की आड़ लेकर कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों को जनता से दूर रहते हुए सियासत करने (टीएमसी अभी तक इसका अपवाद है) की अपनी कमजोरी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्हें देर-सबेर यह समझना होगा कि उनका मुकाबला बुल्डोजर जैसी एक चुनाव मशीनरी से है, जो जीत की राह में किसी नैतिक बाधा से बंधी हुई नहीं है।

ब्लॉग

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026: दुनिया को सचेत उपभोग की ओर प्रेरित करना

प्रताव राव जाधव

आज जब दुनिया अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 मना रही है, मानवता एक निर्णायक सभ्यतागत मोड़ पर खड़ी है। वर्तमान में हम अभूतपूर्व तकनीकी और भौतिक प्रगति के युग में जी रहे हैं, फिर भी हम जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों, बढ़ते मानसिक तनाव, पर्यावरणीय क्षरण और जीवन जीने के अस्थिर तरीकों जैसी चुनौतियों का सामना भी कर रहे हैं। इनमें से कई संकटों के मूल में एक ही चुनौती नज़र आती है- वस्तुओं का अनियंत्रित और बिना सोचे-समझे किया जाने वाला उपभोग।

प्राकृतिक संसाधनों के ज़रुरत से ज्यादा दोहन से लेकर डिजिटल उपयोगिता पर अत्यधिक निर्भरता और अस्थिर जीवनशैली तक, आज आधुनिक समाज संतुलन से लगातार दूर होता जा रहा है। और इसी संदर्भ में, योग न केवल एक प्राचीन स्वास्थ्य अभ्यास के रूप में, बल्कि एक ज़िम्मेदार जीवन जीने के लिए एक कालातीत रूपरेखा के रूप में उभर कर सामने आता है। योग मानवता को आत्म-नियमन, संयम और सचेत विकल्पों की ओर एक शक्तिशाली मार्ग प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने भीतर और अपने आस-पास की दुनिया के साथ सामंजस्य कैसे स्थापित करें।

अत्यधिक उपभोग की वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व ने 'मिशन लाइफ़स्टाइल फ़ॉर एनवायरनमेंट के ज़रिए एक सशक्त दिशा प्रदान की है। सीओपी26 में, प्रधानमंत्री ने एक ऐसे सिद्धांत को सामने रखा, जो योग के दर्शन से गहराई के साथ जुड़ा हैः ₹आज ज़रूरत है सचेत और सोच-समझकर उपयोग करने की, न कि बिना सोचे-समझे और विनाशकारी तरीके से उपभोग करने की।'

हाल ही में, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति-श्रृंखला में आई बाधाओं के बीच, प्रधानमंत्री ने इस अपील का विस्तार करते हुए इसे एक दैनिक नागरिक ज़िम्मेदारी का रूप दिया। उन्होंने नागरिकों को प्रोत्साहित किया कि वे जान-बूझकर ऐसे उपभोग को सीमित करें, जिनसे बचा जा सकता है, जैसे ईंधन बचाना, अनावश्यक ऊर्जा का उपयोग कम करना, और गैर-ज़रूरी खर्चों पर दोबारा विचार करना। यह अपील किसी चीज़ की कमी या अभाव पर आधारित नहीं है, बल्कि, यह सामूहिक सशक्तिकरण, निरंतरता और राष्ट्रीय ज़िम्मेदारी के लिए एक रणनीतिक और नैतिक आह्वान है। जैसा कि उन्होंने हमें याद दिलायाः ₹हर छोटा-बड़ा प्रयास मायने रखता है, ठीक वैसे ही जैसे हर एक बूंद से घड़ा भरता है।₹

ये विचार योग के बुनियादी सिद्धांतों से गहराई से जुड़े हुए हैं। योग दर्शन 'अपरिग्रह' - यानी अनावश्यक चीज़ों को जमा करने से बचना और 'संतोष' यानी अपनी असली ज़रूरतों से संतुष्ट रहना, की बात करता है। ये सिद्धांत मिलकर एक ऐसी सोच पैदा करते हैं, जो लोगों को अंधाधुंध उपभोग से दूर सचेत जीवन की ओर प्रेरित करती है। योग हमें निष्क्रिय उपभोक्ता से बदलकर इस धरती का ज़िम्मेदार रखवाला बनाता है।

पृथ्वी पर इंसानी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तो काफ़ी संसाधन हैं, लेकिन इंसान की असीमित लालच को पूरा करने के लिए नहीं। योग प्रकृति के साथ हमारे आपसी जुड़ाव की भावना को गहरा करके इस जागरूकता को फिर से जगाने में मदद करता है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम करते हैं और जिस स्थिरता की हम तलाश करते हैं, ये सभी एक साझा पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा हैं।

योग का अभ्यास धीरे-धीरे हमारे व्यवहार को भीतर से बदल देता है। यह मन की बेचैनी को शांत करता है, जल्दबाज़ी वाली आदतों को कम करता है और आत्म-अनुशासन को मज़बूत बनाता है। आज की दुनिया, जो पल भर के सुख और अत्यधिक उपभोगवाद से संचालित होती है, उसमें योग वह आंतरिक स्पष्टता पैदा करता है, जिसकी ज़रूरत हमें अपनी असली ज़रूरतों और कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं के बीच फ़र्क समझने के लिए होती है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा आयुष, दोनों मंत्रालयों से जुड़े मंत्री के तौर पर, मैं हर दिन यह देखता हूँ कि योग किस तरह गैर-संक्रामक रोगों (एनसीडी) के खिलाफ एक निवारक सार्वजनिक स्वास्थ्य साधन के रूप में काम करता है। शारीरिक गतिविधि, मानसिक संतुलन और अनुशासित जीवन शैली को बढ़ावा देकर, योग अस्वस्थ आदतों और अत्यधिक चिकित्सीय हस्तक्षेपों पर हमारी निर्भरता को कम करता है। एक योगिक जीवन शैली स्वाभाविक रूप से सादगी, संयम, संतुलित पोषण, कम बर्बादी और संसाधनों के सचेत उपयोग को बढ़ावा देती है, ठीक वही व्यवहारिक बदलाव, जो पर्यावरणीय स्थिरता के लिए ज़रुरी है।

इस प्रकार, योग न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य का एक मार्ग है, बल्कि यह व्यवस्था में जिम्मेदारीपूर्ण जीवन के लिए एक व्यावहारिक ढाँचा भी है। आज, जब योग दुनिया के लिए भारत के सबसे प्रभावशाली योगदानों में से एक बन गया है। यह स्वास्थ्य, सद्भाव और सामूहिक कल्याण की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति भी बन चुका है। जो योग एक प्राचीन सभ्यतागत प्रथा के रूप में शुरू हुआ था, वह आज एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, जो भूगोल, राजनीति, भाषा और संस्कृति की सीमाओं से परे है।

हर साल, कई महाद्वीपों में लाखों लोग योग समारोहों में भाग लेते हैं। वे केवल आसन ही नहीं करते, बल्कि एक स्वस्थ, अधिक संतुलित और टिकाऊ जीवन की साझा आकांक्षा को भी अपनाते हैं। योग निवारक स्वास्थ्य सेवा, मानसिक कल्याण और सचेत जीवन शैली की एक सार्वभौमिक भाषा के रूप में उभरा है। योग के ज़रिए, भारत ने दुनिया को समग्र स्वास्थ्य के लिए एक ऐसा गैर-बाध्यकारी और समावेशी ढाँचा प्रदान किया है, जो आधुनिक चिंताओं का समाधान शाश्वत ज्ञान के साथ करता है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 का यही महत्व है। चूँकि योग दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को छूता है, इसलिए यह बड़े पैमाने पर व्यवहारिक परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए एक बेजोड़ मंच भी प्रदान करता है। योग की सामूहिक भावना के ज़रिए, स्थिरता, संयम और सचेत जीवन-शैली के संदेश अधिक दूर तक पहुँच सकते हैं और लोगों के मन में गहरी छाप छोड़ सकते हैं।

सच्चा कल्याण अकेले अस्तित्व में नहीं हो सकता। मानव स्वास्थ्य, सामुदायिक कल्याण और संपूर्ण ग्रह का स्वास्थ्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। जलवायु परिवर्तन, जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों और पर्यावरण के क्षरण की चुनौतियों के लिए न केवल नीतिगत हस्तक्षेप, बल्कि व्यवहार में परिवर्तन भी ज़रुरी है।

इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर, आइए हम अपनी प्रतिबद्धता को योग मैट से आगे बढ़ाएं। आइए हम योग को केवल दैनिक अभ्यास के रूप में ही नहीं, बल्कि जीवन शैली के रूप में अपनाएं। एक ऐसी जीवन शैली जो सचेत उपभोग, आंतरिक अनुशासन और पारिस्थितिक जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करती है।

आइए हम प्रधानमंत्री के सचेत जीवन जीने के आह्वान पर काम करें और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें, जहां तरक्की और विकास को केवल हमारे उपभोग से नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी से जीने के तरीके से मापा जाए।

अपने आंतरिक वातावरण को बदलकर, हम सब मिलकर अपने ग्रह के बाहरी वातावरण को ठीक कर सकते हैं।

(लेखक आयुष मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं।)

शाकंभरी देवी मंदिर में अचानक आई बाढ़ से तबाही! बह गए लोग, मलबे में दब गईं गाड़ियां...

आर्यावर्त संवाददाता

सहारनपुर। सहारनपुर के शिवालिक क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर परिसर में शुक्रवार को अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। शाकंभरी खोल नदी में अचानक आई तेज बाढ़ आई। देखते ही देखते पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि श्रद्धालुओं में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए। वहीं कई वाहन पानी की तेज बहाव में बह गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेज बहाव की चपेट में आकर ट्रैक्टर-ट्रॉली, कारें, बाइकें, क्रेन और जेनरेटर सहित दर्जनों वाहन बह गए। वहीं मंदिर परिसर और आसपास लगी कई दुकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। अचानक आए पानी से मौके पर चीख-पुकार मच गई और श्रद्धालुओं में दहशत फैल गई। हादसे में दो श्रद्धालुओं के बहने से की सूचना सामने आ रही है, हालांकि प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है। कई अन्य लोगों के फंसे होने की भी आशंका जताई जा रही है।

मौके पर पहुंचे कई आलाधिकारी

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसडीएम बेहट मानवेंद्र सिंह, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इंस्पेक्टर मिर्जापुर सूबे सिंह और इंस्पेक्टर बेहट जितेंद्र कुमार दीक्षित पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं से नदी और बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की जा रही है। मौके पर बचाव टीमों को तैनात कर दिया गया है।

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

बचाव टीमें नदी किनारे और मंदिर परिसर में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटी हैं। पुलिस और प्रशासन लगातार लाउडस्पीकर के जरिए लोगों से नदी और बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील कर रहे हैं। मौके पर हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रशासन द्वारा पूरे क्षेत्र की निगरानी की जा रही है और श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है।

हमीरपुर पुल हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये मुआवजा के निर्देश

आर्यावर्त संवाददाता

हमीरपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी के निर्माणाधीन पुल पर हुई दर्दनाक दुर्घटना में श्रमिकों की मौत पर गहरा शोक प्रकट किया है।

उन्होंने हादसे को अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक बताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है। सीएम ने मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपये तथा घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने गुरुवार देर रात कई जिलों में तेज आंधी-तूफान, बारिश और आकाशीय बिजली से भारी तबाही का भी संज्ञान लेते हुए सभी जिलाधिकारियों को बचाव कार्य तेज करने, नुकसान का आकलन करने और राहत राशि जल्द जारी करने के निर्देश दिए हैं।

हमीरपुर हादसे की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को एसडीआरएफ के साथ मिलकर राहत एवं बचाव अभियान युद्धस्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने घायलों को तत्काल बेहतर उपचार उपलब्ध कराने और प्रभावित परिवारों की हरसंभव मदद सुनिश्चित करने को कहा है। प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। जनपद हमीरपुर में बेतवा नदी पर एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक है।

सीएम योगी ने राहत-बचाव कार्य तेज करने के दिए निर्देश

गुरुवार देर रात आए तेज आंधी-तूफान, बारिश व आकाशीय बिजली से प्रदेश के कई जिलों में भारी नुकसान तथा जनजीवन प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को तत्काल फील्ड में जाकर सर्वे कर नुकसान का आकलन करने और राहत राशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत एवं बचाव कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और हर तीन घंटे में स्थिति की अद्यतन रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही मुआवजा वितरण, राहत शिविरों, बचाव अभियान और अन्य प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करने को भी कहा गया है, ताकि आमजन तक सही और समयबद्ध सूचना पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

भाजपा सरकार के मंत्रियों-विधायकों की जांच की मांग को लेकर कांग्रेस की पत्रकार वार्ता

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से शुक्रवार को एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर भाजपा सरकार के मंत्रियों एवं विधायकों की संपत्तियों, आय के स्रोतों और सरकारी कार्यों की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई गई। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और प्रशासनिक मनमानी के आरोप लगाए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई मंत्री और विधायक भ्रष्टाचार तथा अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोपों से घिरे हैं। कांग्रेस की मांग है कि उनकी संपत्तियों, बैंक खातों और वित्तीय लेन-देन की निष्पक्ष जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराई जाए। उन्होंने कहा कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। पत्रकार वार्ता में महोबा दलित छात्रा प्रकरण का भी उल्लेख किया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में महिलाओं, दलितों और कमजोर वर्गों के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं तथा सरकार इन मामलों में प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही है। साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं और कानून व्यवस्था के मुद्दे भी उठाए गए। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष पर एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वहीं किसान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदीश सिंह ने कहा कि किसान, नौजवान और आम जनता विभिन्न समस्याओं से जूझ रही है।

कार्यक्रम में किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश सिंह, जिला प्रवक्ता सियाराम तिवारी, हरीश त्रिपाठी, सलाउद्दीन हाशमी, अपरबल सिंह, ममनून आलम, आवेश अहमद, अवधेश गौतम और शीतला साहू सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

92 करोड़ का प्रोजेक्ट, 50 गांवों को फायदा...अब हादसे में 6 मौतें, यूपी के हमीरपुर में गिरे पुल की कहानी

आर्यावर्त संवाददाता

हमीरपुर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में निर्माणाधीन पुल गिरने से बड़ा हादसा हो गया। बेतवा नदी पर बन रहे इस पुल का एक पिलर और करीब 25 मीटर लंबा स्लैब तेज आंधी और तूफान के दौरान भरभराकर नदी में गिर गया। हादसे में छह मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन मजदूरों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है।

मोराकांदर गांव के पास उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की देखरेख में द सॉल्टर कंपनी बेतवा नदी पर पुल का निर्माण करा रही है। करीब 92 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस पुल की लंबाई लगभग 700 मीटर है। पुल का निर्माण मार्च 2024 में शुरू हुआ था और इसे दिसंबर 2026 तक पूरा किया जाना है। इस पुल के बन जाने से हमीरपुर के कुडौरा, मोराकांदर, छानी, बेरी, कुरारा समेत करीब 50 गांवों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

मजदूरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला

शुक्रवार तड़के करीब तीन बजे मौसम अचानक खराब हो गया। तेज आंधी और बारिश के बीच पुल की सटरिंग, स्लैब और एक पिलर अचानक ढह गया। उस समय कुछ मजदूर पुल के ऊपर ही मौजूद थे और कुछ मजदूर वहीं आराम कर रहे थे। हादसा इतना अचानक हुआ कि उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। मजदूर जान बचाने के लिए इधर-उधर भागे, जबकि कुछ क्रेन की केबिन में छिप गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने SDRF टीम की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू किया। पुल के ऊपर फंसे तीन मजदूरों को सकुशल नीचे उतार लिया गया। बाकि मलबे में दबे 6 शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

मृतकों की पहचान बांदा जिले के चिल्ला थाना क्षेत्र निवासी लोकेंद्र निषाद, कुलदीप निषाद, भूरागढ़ निवासी सावंत यादव, सभाजीत, हमीरपुर के स्वासा खुर्द निवासी पुष्पेंद्र सिंह चौहान और अचपुरा निवासी 42 वर्षीय राजेश पाल के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों के घरों में कोहराम मच गया। राजेश पाल की बेटी शिवानी ने बताया कि उनके पिता ही परिवार के इकलौते कमाने वाले थे और अब परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है।

पुल निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप

स्थानीय लोगों और ग्रामीणों का आरोप है कि पुल निर्माण में घटिया सामग्री और लापरवाही बरती जा रही थी। घटना के बाद पुल के पास हजारों ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, जिन्हें हटाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। डीएम अभिषेक गोयल ने कहा कि पूरी घटना की जांच कराई जाएगी और हादसे के कारणों का पता लगने के बाद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। साथ ही प्रशासन को राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।

झांसी में स्कार्पियो ने युवक को रौंदा, मौके पर ही हुई मौत

आर्यावर्त संवाददाता

झांसी। यूपी के झांसी जिले में तेज रफ्तार स्कार्पियो ने सड़क किनारे जा रहे एक युवक की जान ले ली। तेज रफ्तार स्कार्पियो ने सड़क किनारे जा रहे मजदूर को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना नवाबाद थाना क्षेत्र स्थित आरटीओ ऑफिस के पास की है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मृतक की पहचान विनोद कुशवाहा निवासी श्याम चौपड़ा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि विनोद मून सिटी इलाके में मजदूरी का काम करके अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार स्कार्पियो ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक कई फीट दूर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर आरोपी वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है।

शादी की खुशियां मातम में बदली

परिजनों के मुताबिक 19 तारीख को विनोद के बेटे के शादी थी और घर में तैयारियां चल रही थीं, लेकिन इस हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही आरोपी चालक को गिरफ्तार किया जाएगा।

कांपा गांव में नदी के किनारे अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र सनसनी

बल्दीराय/सुलतानपुर। हलियापुर थाना क्षेत्र के कापा गांव में गोमती नदी किनारे अमेठी जनपद की सीमा के पास एक अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना डायल 112 के माध्यम से पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी कर शव को कब्जे में ले लिया। शव की शिनाख्त कराने के लिए आसपास के जनपदों में डीसीआर के माध्यम से सूचना भेजी गई है। वहीं सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भी पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।क्षेत्राधिकारी बल्दीराय आशुतोष कुमार ने बताया कि मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल मौके पर कानून व्यवस्था सामान्य बनी हुई है।

बदमाशों के सैलून में फायरिंग से दहशत

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। बदलापुर तहसील अंतर्गत सिंगरामऊ थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गई, जब सैलून में बैठे एक युवक पर बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग कर दी। हमले में युवक बाल-बाल बच गया, जबकि घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। रामीपुर गांव निवासी आशीष मिश्रा मेढ़ा मोड़ स्थित एक सैलून में शेविंग करा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार दो युवक वहां पहुंचे और अचानक उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। पहली गोली युवक के बेहद करीब से गुजरते हुए दीवार में जा लगी, जबकि दूसरी गोली भी निशाना चूक गई। अचानक हुई गोलीबारी से सैलून और आसपास मौजूद लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। आशीष मिश्रा के शोर मचाने पर स्थानीय लोग मौके की ओर दौड़े, लेकिन तब तक हमलावर बाइक से रतासी बाजार की दिशा में फरार हो चुके थे। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 और सिंगरामऊ पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। थाना प्रभारी सैय्यद हसनैन मुंतजार ने बताया कि मामला प्रथम दृष्टया किसी पुराने विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है तथा आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। घटना के बाद इलाके में पुलिस सतर्कता बढ़ा दी गई है।

आंधी और बारिश सब्जी की फसले बर्बाद

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। तेज आंधी और बारिश ने किसानों की मेहनत पर भी पानी फेर दिया। बक्शा क्षेत्र के किसान भारत गुप्ता ने बताया कि खेतों में खड़ी मड़वा की फसल बर्बाद हो गई है। नेनुआ और लौकी जैसी सब्जियों के मचान तेज हवा में टूट गए। वहीं आम की बची-खुची फसल भी पेड़ों से टूटकर गिर गई। किसान सुशील यादव और डॉ. समय बहादुर यादव ने बताया कि बेमौसम बारिश और तेज हवाओं से आम की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं धर्मराज मौर्य और मोहित मौर्य ने बताया कि सब्जियों की फसलें भी काफी प्रभावित हुई हैं, जिससे उत्पादन घटने की आशंका है। दुकानदार दानिश अली ने बताया कि भोर में आई तेज आंधी में उनकी दुकान का टीन शेड उड़ गया। इसके बाद हुई बारिश से दुकान के अंदर रखा सामान भीगकर खराब हो गया। कई अन्य दुकानदारों को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है।बढ़ौना गांव समेत करीब डेढ़ दर्जन गांवों में आठ घंटे से अधिक समय से बिजली गुल रहने के कारण पेयजल संकट खड़ा हो गया है। घरों की पानी टंकियां खाली हो चुकी हैं और लंबे बिजली कटौती के चलते इनवर्टर भी जवाब दे चुके हैं।मोबाइल चार्जिंग और नेटवर्क की समस्या के कारण ग्रामीणों का संपर्क भी प्रभावित हो रहा है। उमस भरी गर्मी में बिजली न होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।सुबह अचानक छाए काले बादलों और तेज हवाओं के चलते दिन में ही अंधेरा जैसा माहौल बन गया। कई जगहों पर पेड़ों की डालियां टूटकर सड़कों पर गिर गईं। बाजारों में लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ा। हालांकि बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत जरूर मिली, लेकिन तेज आंधी और बिजली संकट ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया।

यूपी के हमीरपुर में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ढहा, 6 मजदूरों की मलबे में दबकर मौत

आर्यावर्त संवाददाता

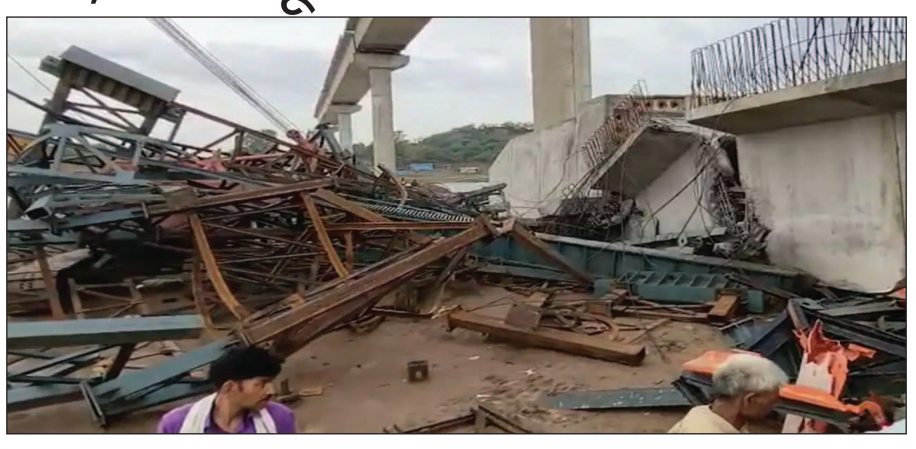

हमीरपुर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बड़ा हादसा हो गया है। बेतवा नदी पर बन रहे एक निर्माणाधीन पुल का हिस्सा अचानक भरभराकर गिर पड़ा, जिससे वहां मौजूद मजदूर मलबे में दब गए। हादसे में अब तक छह मजदूरों की मौत हुई है, जबकि कुछ अन्य लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। राहत और बचाव कार्य जारी है।

कुरारा थाना क्षेत्र में मोरकंदर परसानी से नैथी गांव तक बेतवा नदी पर पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। शुक्रवार अहले सुबह तीन बजे अचानक मौसम खराब हो गया। तेज आंधी और बारिश के बीच पुल की सटरिंग, स्लैब और कोठी ढह गई। बताया जा रहा है कि हादसे के समय कई मजदूर पुल के इसी हिस्से में सो रहे थे, जिसके कारण उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला।

पुल का एक हिस्सा गिर गया

स्थानीय लोगों के मुताबिक तेज हवाओं के साथ जोरदार आवाज आई, जिसके बाद पुल का हिस्सा गिर गया। घटना के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे लोगों को निकालने का प्रयास शुरू किया। बाद में सूचना मिलने पर पुलिस, प्रशासन और SDRF की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंच गईं।

रेस्क्यू टीम जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से लगातार मलबा हटाने में जुटी रही। मौके पर एसडीएम, सीओ समेत कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई है। अधिकारियों का कहना है कि बचाव अभियान लगातार जारी है। आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है।

हादसे में जान गंवाने वाले कौन?

हादसे में जान गंवाने वालों में बांदा जिले के चिल्ला थाना क्षेत्र निवासी लोकेंद्र निषाद, कुलदीप निषाद, भूरागढ़ निवासी सावंत यादव, सभाजीत, हमीरपुर के ललपुर थाना क्षेत्र के स्वासा खुर्द निवासी पुष्पेंद्र सिंह चौहान और अचपुरा निवासी 42 वर्षीय राजेश पाल शामिल हैं।

पुल का निर्माण उनके पैतृक गांव मोरकंदर परसानी के पास कराया जा रहा था। हादसे के बाद निर्माण स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था और निर्माण कार्य में लापरवाही को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है और मृतकों के परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है।

कश्मीर या हिमाचल नहीं...भारत में 'कीवी' का गढ़ है ये जगह, यहां पहुंचना भी आसान

कीवी एक ऐसा फल है, जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें विटामिन सी से लेकर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि भारत में भी कीवी की खूब खेती की जाती है। इस आर्टिकल में हम आपको कीवी का गढ़ बताने जा रहे हैं।

कीवी अब सिर्फ विदेशी फल नहीं बल्कि भारत में भी खूब खाया जाने लगा है। ये फल अपने पोषक तत्वों और फायदों के लिए जाना जाता है। यह विटामिन C, फाइबर, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर हार्ट हेल्थ और खून बढ़ाने में भी मदद करती है। लेकिन बहुत कम ही लोग जानते है कि कीवी को भारत के किस हिस्से में उगाया जाता है। क्योंकि आमतौर पर जब भी कीवी की खेती की बात आती है तो लोगों के दिमाग में हिमाचल या फिर कश्मीर ही आता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी की कीवी कश्मीर या हिमाचल नहीं बल्कि नॉर्थ के एक हिस्से में उगती है।

खास बात यह है कि यहां न सिर्फ बड़े पैमाने पर कीवी की खेती होती है, बल्कि देशभर में सप्लाई होने वाले बेहतरीन कीवी फलों का बड़ा हिस्सा भी यहीं से आता है। चलिए इस आर्टिकल में आपको भी बताते हैं कि भारत में कीवी का गढ़ कौन सा शहर है और वहां पहुंचना कितना आसान है।

भारत में कहां है कीवी का गढ़?

वैसे तो कीवी का गढ़ न्यूजीलैंड है। लेकिन भारत में अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा कीवी उगाई जाती है। जी हां, यही वो जगह है जहां कीवी की खेती की जाती है और पूरे देश में सप्लाई होती है। दिलचस्प बात यह है कि यह जगह अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, हरियाली और शांत वातावरण के लिए भी मशहूर है। यहां की जलवायु कीवी की खेती के लिए इतनी अनुकूल मानी जाती है कि किसानों ने पारंपरिक खेती छोड़कर अब बड़े स्तर पर कीवी उत्पादन शुरू कर दिया है। पिछले कुछ वर्षों में यहां के कीवी की मांग देश के कई बड़े शहरों तक पहुंच चुकी है। स्वाद, गुणवत्ता और प्राकृतिक तरीके से तैयार होने की वजह से यहां का कीवी लोगों को काफी पसंद आती है।

अरुणाचल प्रदेश में कैसे होती है कीवी की खेती?

कीवी उगाने के लिए तापमान न ज्यादा गर्म और न ज्यादा ठंडा चाहिए होता है। अरुणाचल प्रदेश का तापमान इसके लिए परफेक्ट माना जाता है। यहां पर कीवी की खेती पहाड़ी इलाकों में की जाती है। यहां के किसान सबसे पहले अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी का चुनते है। पौधों को लकड़ी और तार के सहारे बेल की तरह ऊपर बढ़ाया जाता है, ताकि उन्हें पर्याप्त धूप और हवा मिल सके। कीवी की खेती में नियमित सिंचाई, जैविक खाद और समय-समय पर छंटाई का खास ध्यान रखा जाता है। इसके बाद ही निकलती है अच्छी क्वालिटी की कीवी।

कीवी के फायदे और न्यूट्रिशन

कीवी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। हेल्थलाइन के मुताबिक, इसमें फाइबर, पोटैशियम, फोलेट और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करते हैं। 100 ग्राम कीवी में लगभग 60 से 65 कैलोरी, 3 ग्राम फाइबर और भरपूर मात्रा में विटामिन C मौजूद होता है। यही वजह है कि इसे इम्यूनिटी बढ़ाने वाला सुपरफूड भी कहा जाता है। इसमें एक्टिनिडिन नाम का एंजाइम भी होता है, जो भोजन को पचाने के प्रोसेस को बेहतर बनाता है। कीवी इम्यूनिटी बढ़ाने, पेट की समस्याओं से कम करने और हार्ट को हेल्दी बनाने में सबसे ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है। विटामिन सी और ई होने की वजह से स्किन और बालों के लिए बेनिफिशियल है।

अरुणाचल प्रदेश की खासियत

अरुणाचल प्रदेश एक बेहद खूबसूरत जगह है, जहां आपको बर्फ से ढके पहाड़, घने जगंल और शांत वातावरण देखने को मिल जाएगा। भारत में सबसे पहले इसी जगह पर सूर्योदय होता है, जिसकी वजह से इसे उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। पूरे साल अरुणाल प्रदेश में टूरिस्ट का आना-जाना लगा रहता है। यहां देखने के लिए कई जगहे हैं, जिसमें शामिल है तवांग मठ, ज़ीरो वैली, सेला पास, नमदाफा नेशनल पार्क और बोमडिला। अरुणाचल प्रदेश आना भी आसान है। आप बस, ट्रेन या फिर फ्लाइट से यहां पहुंच सकते हैं।

गर्मियों में पसीने की वजह से हो जाती है घमोरी? बचाव के लिए अपनाएं ये सुझाव

गर्मियों में सबसे ज्यादा परेशान करता है पसीना, जो उमस की वजह से बहुत बढ़ जाता है। ज्यादा पसीना निकलने के कारण त्वचा पर घमोरियां हो सकती हैं। इस समस्या की वजह से त्वचा पर लाल दाने, खुजली या जलन होती है। इसके उत्पन्न होने पर तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। हालांकि, अगर आप घमोरियों से बचना चाहते हैं तो इन 5 टिप्स का पालन करें। इनके जरिए आपका स्वास्थ्य सही रहेगा और आपको ज्यादा पसीना भी नहीं आएगा।

ढीले-ढाले सूती कपड़े पहनें

गर्मियों में ढीले-ढाले कपड़े पहनना सबसे अच्छा होता है। तंग कपड़े पहनने से पसीना निकलने की जगह नहीं मिलती, जिससे घमोरियां हो सकती हैं। सूती कपड़े इस मौसम में सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि ये त्वचा को हवा लगने देते हैं और पसीने को सोख लेते हैं। इसके अलावा ढीले कपड़े पहनने से त्वचा को आराम मिलता है और गर्मी से होने वाली जलन से बचाव होता है। इसलिए, हमेशा सूती और ढीले कपड़े ही पहनें।

रोजाना नहाएं

रोजाना नहाना एक अच्छी आदत है, जो गर्मियों के दौरान खासतौर से जरूरी है। इससे न केवल शरीर की गंदगी दूर होती है, बल्कि पसीने के कारण होने वाली घमोरियों से भी छुटकारा मिलता है। नहाने के लिए हल्का गुनगुना पानी इस्तेमाल करें और साबुन की जगह हल्के जेल या फोम का उपयोग करें। इससे आपकी त्वचा साफ रहेगी और तरोताजा महसूस होगा। इसके अलावा नहाने के बाद त्वचा को अच्छी तरह से सुखाना न भूलें।

त्वचा को नमी दें

नहाने के बाद त्वचा पर मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है। यह न केवल त्वचा को नमी देता है, बल्कि उसे मुलायम भी रखता है। इसके लिए हल्का और बिना खुशबू वाला मॉइस्चराइजर चुनें, जो आपकी त्वचा के प्रकार के अनुसार हो। इससे घमोरी होने की संभावना कम होती है और त्वचा पर ताजगी बनी रहती है। नियमित रूप से मॉइस्चराइजर लगाने से त्वचा की नमी बरकरार रहती है और वह स्वस्थ दिखती है।

धूप से बचाव करें

सूरज की हानिकारक किरणें भी घमोरी का कारण बन सकती हैं, इसलिए बाहर जाने से पहले अपनी त्वचा पर धूप से बचाव करने वाली क्रीम लगाएं। यह आपकी त्वचा को धूप से बचाती है और जलन होने से रोकती है। हर 2-3 घंटे बाद इसे दोबारा लगाना न भूलें, खासकर अगर आप लंबे समय तक बाहर रह रहे हैं। इसके अलावा सूरज की सीधी किरणों से बचने के लिए टोपी या छाते का इस्तेमाल करें।

पानी पीते रहें

शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी है, ताकि पसीना आसानी से निकल सके और शरीर ठंडा रहे। दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीएं और नारियल पानी, ताजे फलों का रस या इलेक्ट्रोलाइट पेय भी शामिल करें। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और घमोरियां होने की संभावना कम होगी।

रोजाना बर्फ खाने से हो सकते हैं ये 5 स्वास्थ्य जोखिम, आज ही बदलें यह आदत

बर्फ खाने की आदत कई लोगों को होती है। यह आदत भले ही आपको मजेदार लगे, लेकिन इसके कई स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं। बर्फ खाने से आपके मुंह, गले और पेट पर बुरा असर पड़ सकता है। इस लेख में हम आपको रोजाना बर्फ खाने से होने वाले कुछ गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में बताएंगे, ताकि आप इस आदत को सुधार सकें और अपने स्वास्थ्य का बेहतर तरीके से ख्याल रख सकें।

दांतों को हो सकता है नुकसान

रोजाना बर्फ खाने से आपके दांतों को काफी नुकसान पहुंच सकता है। बर्फ बहुत ठंडी होती है, जो दांतों की ऊपरी परत को कमजोर कर सकती है। इससे दांत संवेदनशील हो जाते हैं और दर्द भी हो सकता है। इसके अलावा बर्फ चबाने से दांतों में दरारें पड़ सकती हैं, जिससे कीड़े लग सकते हैं। इसलिए, बेहतर होगा कि आप बर्फ खाने की आदत को छोड़ दें और पानी को प्राथमिकता दें।

गले में हो सकता है संक्रमण

बर्फ खाने से गले में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ठंडी बर्फ गले के अंदरूनी हिस्से पर असर डाल सकती है, जिससे सूजन और जलन हो सकती है। इससे गले में खराश, खांसी और दर्द भी हो सकता है। इसके अलावा ठंडी बर्फ खाने से गले की नसें सिकुड़ सकती हैं, जिससे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ऐसे में आपको बात करने या खाने-पीने में भी असुविधा झेलनी पड़ सकती है।

पेट पर पड़ सकता है बुरा असर

बर्फ खाने से पेट पर भी बुरा असर पड़ सकता है। ठंडी बर्फ पेट के अंदरूनी हिस्से को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे उल्टी और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा बर्फ खाने से पेट में गैस बन सकती है, जिससे पेट दर्द और अपच की समस्या हो सकती है। बर्फ पेट में जा कर कुछ देर के लिए ठंडक तो प्रदान करती है, लेकिन इसका बाद में जो असर होता है, वो अच्छा नहीं होता है।

शरीर का तापमान हो सकता है असंतुलित

रोजाना बर्फ खाने से शरीर का तापमान असंतुलित हो सकता है। इससे शरीर को सामान्य तापमान पर वापस आने में समय लग सकता है, जिससे ठंड लग सकती है। इसके अलावा बर्फ खाने से शरीर में सूजन बढ़ सकती है, जिससे कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए, बेहतर होगा कि आप बर्फ खाने की आदत को छोड़ दें और पानी को प्राथमिकता दें। अगर गर्मी महसूस हो रही हो तो ठंडा पानी पी लें।

दिल की सेहत पर पड़ सकता है असर

रोजाना बर्फ खाने से दिल की सेहत पर भी असर पड़ सकता है। बर्फ खाने से खून की नसें सिकुड़ सकती हैं, जिससे खून का दबाव बढ़ सकता है और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा बर्फ खाने से दिल की धड़कन भी अनियमित हो सकती है, जो एक खतरे की घंटी होती है। इसलिए, बेहतर होगा कि आप बर्फ खाने की आदत को छोड़ दें और पानी को प्राथमिकता दें।

ओवरथिंकिंग और घबराहट ने उड़ा दी है नींद? अपनाएं ये 3 अनोखे तरीके

नींद की कमी सिर्फ मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डालती है। लेकिन आजकल ओवरथिंक और बैचेनी की वजह से कई लोगों को रात को जल्दी नींद नहीं आती है। यहां हम 3 ऐसे अनोखे तरीके बता रहे हैं, जो नींद लाने में मदद कर सकते हैं।

रात में बार-बार करवट बदलना, अचानक दिल की धड़कन तेज महसूस होना या बिना किसी वजह के मन में डर और तनाव महसूस होना आजकल बहुत आम समस्या बन चुकी है। मोबाइल और सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल भी दिमाग को लगातार एक्टिव रखता है, जिससे शरीर थका होने के बावजूद मन शांत नहीं हो पाता। कई बार लोग नींद न आने पर देर रात तक फोन चलाते रहते हैं, लेकिन इससे समस्या और बढ़ जाती है।

नींद पूरी न होने का असर सिर्फ अगले दिन की थकान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में जरूरी है कि रात को सोने से पहले कुछ ऐसी आदतें अपनाई जाएं, जो दिमाग को शांत करें और शरीर को रिलैक्स करने में मदद कर सकती हैं। चलिए जानते हैं उनके बारे में।

Brain Dump Technique का करें यूज

Baylor University की रिसर्च बताती है कि अगर आपको रात को नींद नहीं आती है तो ब्रेन डंप तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अपने दिमाग में चल रही बातों को एक कॉपी पर लिखना होता है। रिसर्च में पाया गया है कि सोने से पहले 5 मिनट तक अपनी टेंशन, टू-डू लिस्ट या मन की बातें लिखने से दिमाग हल्का महसूस करता है और नींद जल्दी आने लगती है। इससे दिमाग को एक तरह का 'closure signal' मिलता है और ओवरथिंकिंग धीरे-धीरे कम होने लगती है।

ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें

ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से भी नींद की क्वालिटी को सुधारा जा सकता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि धीमी और गहरी सांसें शरीर के स्ट्रेस रिस्पॉनंस को कम करती हैं। इसे करे के लिए सबसे पहले 4 सेकंड तक नाक से सांस लें, 7 सेकंड तक सांस रोकें, 8 सेकंड तक धीरे-धीरे मुंह से सांस छोड़ें। इसे 4 से 5 बार दोहराएं यह तरीका दिल की धड़कन को शांत करने और शरीर को स्लीप मोड में लाने में मदद कर सकता है।

पैरों को गर्म रखना भी आएगा काम

यह थोड़ा अलग लेकिन रिसर्च-बेस्ड तरीका है। स्टडीज बताती हैं कि सोने से पहले पैरों को हल्का गर्म रखने से बॉडी टेमप्रेचर रेगुलेशन बेहतर होता है, जिससे नींद जल्दी आने में मदद मिल सकती है। ऐसे में आपको रात को सोने से पहले गुनगुने पानी में 10 मिनट पैर डुबोकर रखें या हल्के गर्म मोजे पहन लें। इससे शरीर को रिलैक्सेशन का संकेत मिलता है और बेचैनी कम महसूस हो सकती है।

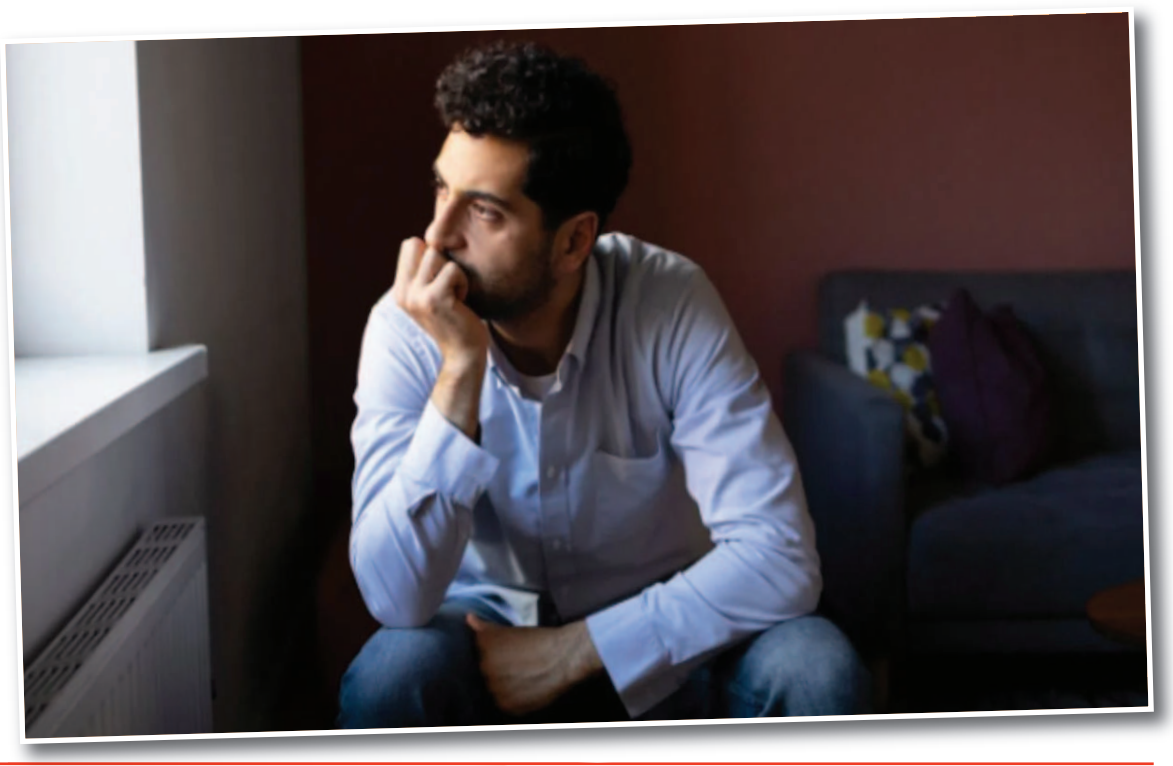

सोलर पैनल लगवाने वालों के लिए जरूरी खबर, 1 जून से बदल रहा है नियम

1 जून 2026 से सरकार एक नया नियम (ALMM-II) लागू करने जा रही है। इसके बाद सोलर सिस्टम लगवाना ₹3000 से ₹9000 तक महंगा हो सकता है। हालांकि, राहत की बात यह है कि 'पीएम सूर्य घर योजना' की सरकारी सब्सिडी पहले की तरह जारी रहेगी।

भयंकर गर्मी से राहत पाने के लिए और बिजली का बिल जीरो करने के मकसद से अगर आप भी घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहद अहम खबर है। दरअसल, सरकार 1 जून 2026 से सोलर इंडस्ट्री में एक नया नियम लागू करने जा रही है। इस नए बदलाव (ALMM लिस्ट-II) के तहत अब सोलर पैनल के साथ-साथ उसमें इस्तेमाल होने वाले 'सोलर सेल' का भी सरकारी मानकों पर खरा उतरना अनिवार्य होगा। इस फैसले का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है, क्योंकि आने वाले दिनों में सोलर सिस्टम लगवाने की लागत बढ़ सकती है। हालांकि, राहत की बात यह है कि 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के तहत मिलने वाली सब्सिडी पहले की तरह जारी रहेगी।

क्या है 1 जून से लागू होने वाला नया नियम?

अब तक बाजार में ये नियम लागू था कि घरों में जो सोलर पैनल लगाए जाते हैं, वे सरकार की मंजूरशुदा लिस्ट (ALMM List-I) से प्रमाणित होने चाहिए। लेकिन अब सरकार ने इस व्यवस्था को थोड़ा सख्त कर दिया है। 1 जून से लागू होने वाले नए नियम के तहत, सोलर पैनल के भीतर लगने वाले छोटे-छोटे 'सोलर सेल' भी सरकार की अप्रूव्ड लिस्ट (List-II) में शामिल होने चाहिए। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस डेडलाइन को किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसका मकसद घटिया क्वालिटी के विदेशी उपकरणों पर रोक लगाना है।

लागत में कितनी होगी बढ़ोतरी?

नए मानकों के लागू होने से बाजार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि घरेलू सोलर सेल की अनिवार्यता से पैनल की कीमतों में इजाफा होना लगभग तय है। अगर आप 1 किलोवाट (1kW) का सोलर सिस्टम लगवाते हैं, तो आपको पहले के मुकाबले करीब ₹3000 अतिरिक्त खर्च करने पड़ सकते हैं। इसी गणित के हिसाब से 2 किलोवाट के सेटअप पर ₹6000 तथा 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाने पर लगभग ₹9000 तक का बोझ आपकी जेब पर पड़ सकता है। बाजार में अगर अप्रूव्ड सेल की सप्लाई कम हुई, तो यह खर्च और भी ज्यादा बढ़ सकता है।

क्या खत्म हो जाएगी सरकारी सब्सिडी?

बाजार में नियम बदलने की खबर के साथ ही सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रामक बातें भी फैल रही हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि सरकार अब सब्सिडी बंद कर देगी, लेकिन यह खबर पूरी तरह से बेबुनियाद है। 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के तहत आम जनता को मिलने वाली आर्थिक मदद बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। ग्राहकों को 1 किलोवाट पर ₹30,000, 2 किलोवाट पर ₹60,000 तथा 3 किलोवाट या उससे ऊपर के सिस्टम पर अधिकतम ₹78,000 की छूट पहले की तरह ही मिलती रहेगी। कई राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से टॉप-अप सब्सिडी देती रहेंगी। बदलाव सिर्फ इतना होगा कि अब सब्सिडी का फायदा लेने के लिए कागजी कार्रवाई, वेंडर का चयन तथा जांच प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा सख्त हो जाएगी।

उपभोक्ताओं के लिए क्या हैं विकल्प?

अगर आप नया सिस्टम लगवाने जा रहे हैं, तो आपके सामने मुख्य रूप से दो रास्ते हैं। पहला विकल्प 'सब्सिडी रूट' है। यह उन परिवारों के लिए सबसे मुफीद है जो अपना बिजली बिल खत्म करना चाहते हैं। हालांकि, इसमें आपको सरकार द्वारा तय की गई तकनीक व कंपोनेंट्स ही चुनने होंगे। दूसरा रास्ता 'फ्रीडम रूट' है, जिसमें आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलती। यह उनके लिए बेहतर है जो एकदम लेटेस्ट ग्लोबल तकनीक (जैसे HJT, HDT या लिथियम बैटरी) का इस्तेमाल करना चाहते हैं। भारी बिजली कटौती वाले इलाकों के लिए यह एक मजबूत और टिकाऊ विकल्प है। इसमें शुरुआती लागत भले ही ज्यादा हो, लेकिन लंबे समय में इसका परफॉर्मेंस काफी शानदार रहता है।

आईटीआर-2 फॉर्म और एक्सेल यूटिलिटी पोर्टल पर उपलब्ध, देखें रिटर्न दाखिल करने का तरीका

आयकर विभाग ने 27 मई, 2025 को ई-फाइलिंग आईटीआर पोर्टल पर असेसमेंट ईयर (A.Y.) 202627 के लिए आईटीआर-2 की ऑनलाइन फाइलिंग और एक्सेल यूटिलिटी शुरू कर दी है। इसका मतलब है कि छात्र, पेंशनभोगी, वेतनभोगी कर्मचारी और अन्य लोग, जिन्हें आयकर ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, अब अपना ITR फाइल करना शुरू कर सकते हैं। आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ऑफलाइन एक्सेल यूटिलिटी, ऑनलाइन यूटिलिटी या आईटीआर ई-फाइलिंग वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर 2026-2027 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2026 या उससे पहले है। टैक्स ईयर 2026-2027 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2027 है।

हालांकि, अगर आपकी कुल सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम है, तो आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी सैलरी से इनकम 12 लाख रुपए है, तो आपको आईटीआर फाइल करना होगा। हालांकि, नई टैक्स व्यवस्था के तहत सेक्शन 87ए की बढ़ी हुई टैक्स छूट की वजह से, आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा।

कौन फाइल कर सकता है ITR-2?

चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्सविन के को-फाउंडर अभिषेक सोनी ने ईटी की रिपोर्ट में कहा कि आईटीआर-2 उन इंडीविजुअल्स और हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए है, जिनकी आय किसी बिजनेस या पेशे से नहीं होती, लेकिन जिनकी आय का ढांचा ज्यादा जटिल होता है। इसमें सैलरी या पेंशन से होने वाली इनकम, कई मकानों से होने वाली इनकम, और निवेश या प्रॉपर्टी की सेल्स से होने वाले कैपिटल गेन या लॉस (दोनों, शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म) से होने वाली इनकम शामिल है।

इसके अलावा, जिन व्यक्तियों की कुल आय 50 लाख रुपए से ज्यादा है, साथ ही जो नॉन-रेसिडेंट हैं या 'रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट' (RNOR) हैं, वे आईटीआर-1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें अनिवार्य रूप से आईटीआर-2, आईटीआर-3, या उनके लिए लागू कोई अन्य आईटीआर फाइल करना पड़ता है।

सोनी कहते हैं कि आईटीआर-2 का इस्तेमाल

'अन्य सोर्स' से होने वाली इनकम की जानकारी देने के लिए भी किया जा सकता है। इसमें लॉटरी, रेसकोर्स, या अन्य कानूनी जुआ गतिविधियों से होने वाली जीत, और साथ ही 5,000 रुपए से ज्यादा की कृषि आय शामिल है।

इसके अलावा, जो व्यक्ति किसी कंपनी में डायरेक्टर के पद पर हैं, या जिन्होंने 'अनलिस्टेड इक्विटी शेयर' में निवेश किया है, उन्हें अपनी आय के स्तर की परवाह किए बिना, अनिवार्य रूप से ITR-2 फाइल करना होता है।

किन बातों से बचें ITR-2 फाइलर्स

अभिषेक सोनी मीडिया रिपोर्ट में कहते हैं कि ITR-2 फाइलिंग में अक्सर ज्यादा पेचीदगियां होती हैं, और टैक्सपेयर्स अक्सर रेजिडेंशियल स्टेटस, कैपिटल गेन्स की रिपोर्टिंग, और विदेशी एसेट्स के खुलासे जैसे मामलों में गलतियां कर देते हैं। शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स का गलत कैटेगराइजेशन, या शेड्यूल 112ए में डिटेल में जानकारी न देना, एक आम समस्या है।

सोनी के अनुसार, रेजिडेंट टैक्सपेयर्स कभी-कभी शेड्यूल एफए में विदेशी एसेट्स और विदेशों में मौजूद खातों की अनिवार्य रिपोर्टिंग को नजरअंदाज़ कर देते हैं, जिससे कंप्लायंस से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसी तरह, रेजिडेंशियल स्टेटस को गलत तरीके से तय करना—चाहे वह रेजिडेंट हो, नॉन-रेजिडेंट हो, या RNOR हो—गलत टैक्स कैलकुलेशन और कंप्लायंस की ज़रूरी शर्तों को पूरा न कर पाने का कारण बन सकता है। जैसे कि विदेशी टैक्स क्रेडिट के लिए फॉर्म 67 फाइल न करना।

अचल संपत्ति, बैंक बैलेंस, शेयर, गहने और वाहन जैसे एसेट्स की रिपोर्टिंग में भी गलतियां होना आम बात है। टैक्सपेयर्स को अपनी इनकम की कम या ज्यादा रिपोर्टिंग से बचने के लिए, अपनी दी गई जानकारियों का फॉर्म 26AS और AIS से सावधानीपूर्वक मिलान करना चाहिए।

सोनी के अनुसार, एक और आम गलती है नुकसान को आगे ले जाने (carry-forward) और उसकी भरपाई (set-off) करने के तरीके को ठीक से न संभालना। इसमें शेड्यूल CFL और शेड्यूल BFLA को सही तरीके से न भरना, या कैपिटल गेन्स में हुए नुकसान को आगे ले जाने के लिए तय समय-सीमा के भीतर फाइलिंग न करना शामिल है।

इसके अलावा, टैक्सपेयर्स को यह भी पक्का करना चाहिए कि उनके पते और एम्प्लॉयर (नियोक्ता) से जुड़ी निजी जानकारी अपडेटेड हो, खासकर तब जब उन्होंने साल के दौरान अपनी नौकरी या शहर बदला हो। कुल मिलाकर, ITR-2 फाइलिंग में गलतियों से बचने के लिए इनकम का सावधानीपूर्वक कैटेगराइजेशन, सही जानकारी देना, और आधिकारिक टैक्स डिटेल्स के साथ पूरी तरह से मिलान करना बेहद जरूरी है।

अमेरिका की चेतावनी के बाद ओमान का होर्मुज टोल से इनकार, बोला-ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ओमान ने वॉशिंगटन को भरोसा दिलाया है कि उसका ईरान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर टोल लगाने का कोई इरादा नहीं है और वो दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहता है। व्हाइट हाउस में एक ब्रीफिंग के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए, बेसेंट ने कहा कि उनकी ओमान के राजदूत से फोन पर बात हुई थी और उन्होंने यह साफ कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर टोल लगाने का प्रस्ताव बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। उन्होंने बताया कि ओमान ने भरोसा दिलाया है कि वह ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहता जिससे लोगों की सुरक्षा और देश की अर्थव्यवस्था को कोई खतरा हो।

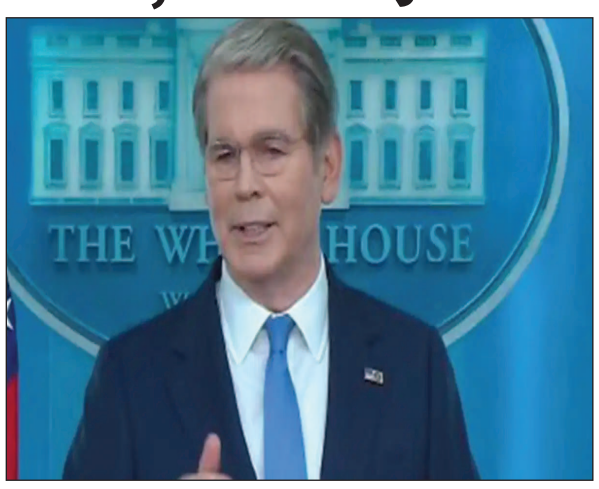

उन्होंने बताया कि ओमान राजदूत ने फोन पर बातचीत के दौरान कहा कि हमारे देशों के बीच 200 सालों से अच्छे संबंध रहे हैं। वह इन संबंधों को और 200 साल तक बनाए रखना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि ये बात तो शुरू ही नहीं हो सकती और वो ये जोखिम नहीं उठाना चाहते थे कि ओमान के लोगों या ओमान के वित्तीय संस्थानों पर प्रतिबंध लग जाएं।

ओमान को दी थी चेतावनी

ये बात तब सामने आया जब स्कॉट बेसेंट ने ओमान को चेतावनी दी कि वह ईरान के साथ मिलकर होर्मुज जलडमरूमध्य में टोल व्यवस्था शुरू करने में किसी भी तरह से शामिल न हो। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन ऐसे प्रयासों को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। X पर एक पोस्ट में, बेसेंट ने कहा कि अमेरिका ऐसी व्यवस्था को शुरू करने में मदद करने वाली किसी भी संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा और उन्होंने विशेष रूप से ओमान को चेतावनी दी।

ट्रंप ने क्या कहा था?

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का एक अहम एनर्जी कॉरिडोर है। पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से ही ईरान और अमेरिका के बीच भू-राजनीतिक तनाव का केंद्र रहा है। इसकी वजह तेल और गैस की शिपमेंट के लिए इसका स्ट्रैटेजिक महत्व काफी है। ओमान का ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस चेतावनी के एक दिन बाद सामने आया है। ट्रंप ने ओमान को इस स्ट्रैटेजिक जलमार्ग से जुड़ी बातचीत में दखल न देने को कहा था। साथ ही, उन्होंने एक ऐसे शॉर्ट-टर्म समझौते के विचार को भी खारिज कर दिया था, जिससे ईरान और ओमान को इस अहम जलमार्ग पर कंट्रोल मिल जाता। वो भी एक ऐसा जलमार्ग जिस पर दुनिया की तेल और गैस की सप्लाई काफी हद तक निर्भर करती है।

भारत से ज्यादा फॉलोअर्स किसी और देश में नहीं... नेतन्याहू ने जमकर की हिंदुस्तान की तारीफ, पाकिस्तान पर बरसे

तेल अवीव, एजेंसी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बताने का मौका नहीं छोड़ते हैं। इसलिए उनकी ओर से दिल्ली और तेल अवीव के बीच के मजबूत समर्थन का दावा करते हुए देखा जाता है। इसी कोशिश को एक बार फिर से पूरा करते हुए वेस्ट बैंक में एक कॉन्फ्रेंस में भारत की तारीफ करते हुए नजर आए। नेतन्याहू ने भारत नाम को विशाल शक्ति बताते हुए इजराइल के साथ उसके अनोखे रिश्ते के बारे में बताया। नेतन्याहू ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में हमें अपनी वैधता को लेकर दिक्कतें आती हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में इजराइल के लिए जबरदस्त समर्थन है, सचमुच बहुत जबरदस्त। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारत से हमारे फॉलोअर्स (समर्थक) कहीं और के मुकाबले सबसे ज्यादा हैं। यह पहली बार नहीं है जब नेतन्याहू ने भारत में अपनी लोकप्रियता के बारे में बढ़-चढ़कर बात की है। उन्होंने 2018 में अपनी पत्नी सारा के साथ नई दिल्ली की अपनी पिछली यात्रा को एक 'प्रेम उत्सव' बताया था। उन्होंने कहा था कि भारतीयों के मन में इजराइल के लिए बहुत सम्मान है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि कुछ जगहें ऐसी हैं जहां इजराइल का अब भी सम्मान किया जाता है। भारत की आबादी 1.4 अरब है, और वहां इजराइल बहुत लोकप्रिय है। यहां पीएम मोदी का बड़े स्नेह के साथ स्वागत किया गया था। जब मैं अपनी पत्नी के साथ भारत गया था, तो वो एक प्रेम उत्सव जैसा था। इजराइल के पीएम का बयान इस समय आया है जब अमेरिकी लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता में कमी देखी गई है। अप्रैल में जारी प्यू रिसर्च सेंटर के हालिया सर्वे के मुताबिक, 60% अमेरिकी वयस्क इजराइल के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। पिछले साल ये आंकड़ा 53% था।आधे से ज्यादा अमेरिकी वयस्कों (59%) को नेतन्याहू पर दुनिया के मामलों में सही काम करने का बहुत कम या बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पिछले साल ये आंकड़ा 52% था। नेतन्याहू ने अपनी लोकप्रियता में आई गिरावट के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। उसी इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तान पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अमेरिकी जनता की राय में इजराइल-विरोधी भावना को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।

पाकिस्तान गारंटर, तेहरान में होगा 300 अरब डॉलर का निवेश...ईरान-अमेरिका डील की पूरी डिटेल

तेल अवीव, एजेंसी। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते की पूरी डिटेल सामने आ गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के हस्ताक्षर के बाद यह समझौता अमल में आ जाएगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति और वार्ता दल के प्रमुख जेडी वेंस का कहना है कि समझौते पर हमने प्रगति की है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यह समझौता 60 दिनों के लिए होगा। इसके तहत कतर से ईरान को जब्त पैसे मिलेंगे, बदले में ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से खोलेगा। सऊदी अरब की अल हदथ अखबार के मुताबिक समझौते को 2 फेज में पूर्ण किया जाएगा। पहले फेज में सिर्फ अंतरिम समझौते के कुछ बिंदुओं को अमल में लाया

जाएगा। इसके बाद पूर्ण समझौते के लिए बैठकें आयोजित की जाएगी। अंतरिम समझौते में पाकिस्तान को गारंटर बनाने की बात कही गई है। वहीं ईरान ने परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। मेहर समाचार एजेंसी ने एक रिपोर्ट में पाकिस्तान सूत्रों के हवाले से डील के करीब होने की जानकारी दी है।

परमाणु डील में और क्या-क्या है?

अमेरिकी आउटलेट Axios के मुताबिक 60-दिन के MoU में यह कहा गया है कि होर्मुज स्ट्रेट से शिपिंग बिना रोक-टोक होगी। इसका मतलब है कि कोई टोल नहीं लगेगा और कोई परेशानी नहीं होगी। ईरान ने 30 दिन में होर्मुज को क्लीन करने की बात कही है। ईरान ने समझौते के तहत परमाणु हथियार नहीं बनाने का वादा किया है। साथ उसके 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम का क्या होगा, इसको लेकर मुख्य समझौते के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। यानी अभी संवर्धित यूरेनियम ईरान में ही रहेगा।

ईरान को कतर से कुछ जब्त पैसे मिलेंगे। यह रकम कितनी होगी? इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। दूसरी तरफ ईरान चाहता है कि उसे डील के वक्त कम से कम 12 बिलियन डॉलर की राशि दी जाए। ईरान राहत एवं बचाव कार्यों में इसे खर्च करना चाहता है।

ट्रंप 300 अरब डॉलर का निवेश करेंगे

न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान से अगर परमाणु समझौता हो जाता है तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद 300 अरब डॉलर निवेश कर सकते हैं। ट्रंप तेल और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये निवेश करेंगे। पिछले साल जब ओमान में समझौते पर बात हो रही थी, तब ईरान ने अमेरिका को यह ऑफर दिया था।

ईरान का कहना था कि ट्रंप चाहे तो कच्चे तेल के उत्पादन में अमेरिकी कंपनियों से निवेश करवा सकते हैं। हालांकि, उस वक्त समझौते पर बात नहीं बनी थी।

पुतिन कैसे जिएं 150 साल, इसी पर 2500 अरब रुपए खर्च कर रहा है रूस

मॉस्को, एजेंसी। सितंबर 2025 में बीजिंग से सामने आए शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के एक लीक ऑडियो ने उम्र बढ़ाने के मसले पर दुनियाभर में नई बहस छेड़ दी। सवाल उठने लगे कि क्या मनुष्य ऐसा कोई प्रयोग कर सकता है, जिससे आम नागरिकों की उम्र बढ़ाई जा सके। दरअसल, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यह बातचीत कर रहे थे कि इंसान की उम्र को 150 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद यह भी चर्चा तेज हो गई कि क्या पुतिन और जिनपिंग खुद 150 साल तक जीना चाहते हैं?

अब रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन से जो नई जानकारी आई है, उसके मुताबिक रूसी राष्ट्रपति आवास उम्र बढ़ाने के तौर-तरीकों की खोज के लिए एक शोध करवा रहा

है। इस शोध पर 26 अरब डॉलर खर्च (2,500 अरब रुपए) करने की तैयारी है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसकी रिपोर्ट दी है।

रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन इस वैज्ञानिक प्रोजेक्ट की खुद देखरेख कर रहे हैं। वहीं प्रोजेक्ट का नेतृत्व पुतिन की बेटी मारिया वोरोंत्सोवा एंडोक्रिनोलॉजिस्ट), और रूस के कुरचातोव इंस्टीट्यूट के प्रमुख मिखाइल कोवैल्चुक कर रहे हैं।

रूस में किस तरह की तैयारी है?

2024 में रूस के वैज्ञानिकों ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था। इसकी शुरुआत काफी धीमी थी, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ ली है। प्रोजेक्ट के तहत 3 प्रमुख काम किए जा रहे हैं-

1- जीन थेरेपी के जरिए सेलुलर एजेइंज को धीमा करना है। कोशिश यह है कि इस थेरेपी के जरिए बुढ़ापे को बढ़ाने वाले जीन को खत्म किया जाए।

2- 3D बायोप्रिंटिंग प्रोसेस के जरिए खराब हो चुके इंसानी अंग को फिर से तैयार करना। पुतिन का कहना था कि अगर अंग को बदल दिया जाए तो उम्र बढ़ सकती है।

3- जीन-मैच्ड छोटी सूअर में मानव अंगों का विकास के जरिए इस प्रयोग को सफल करने की कोशिश की जा रही है। रूस के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने चूहे का थाइरॉयड ग्लैंड और मानव कार्टिलेज ऊतक बायोप्रिंट किए हैं। रूस के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यह प्रक्रिया साल 2030 तक पूरी हो सकती है।

प्रोजेक्ट को काफी सीक्रेट रखा गया है

उम्र बढ़ाने के तौर-तरीकों को खोजने वाले इस प्रोजेक्ट को काफी सीक्रेट रखा गया है। 73 साल के पुतिन इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। उनके करीबी वैज्ञानिकों को ही इस प्रोजेक्ट में लगाया गया है। रूस उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रहा है। रूस में पुरुषों की औसत आयु 68 साल है, जो यूरोप के किसी भी देश से कम है। यूरोप में पुरुषों की औसत आयु 78 साल है।

3 महीने के अंदर सुनाए जाएं लंबित फैसले, सुप्रीम कोर्ट का सभी हाई कोर्ट को निर्देश, जमानत के आदेशों पर भी दिया ऑर्डर

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट फैसले सुनाने में देरी को लेकर सख्त निर्देश दिया है। SC ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि सभी मामलों का निपटारा जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। CJI सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी HC को तीन महीने के भीतर लंबित फैसला सुनाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जमानत आदेश उसी दिन या फैसले होने पर अगले दिन सुनाया जाए। देश की सर्वोच्च अदालत ने निचली अदालतों को नियमित जमानत आदेशों की तत्काल सूचना देने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जमानत प्राप्त विचाराधीन कैदियों को औपचारिकताओं के अधीन उसी दिन रिहा किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी निर्णय सुनाए जाने के 24 घंटे के भीतर HC की वेबसाइटों पर अपलोड किए जाने चाहिए। फैसले के मुख्य भाग के सुनाए जाने की तिथि को ही फैसला सुनाए जाने की तिथि माना जाएगा।

'समय पर फैसला सुनना जरूरी है'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि HC प्राथमिक संस्थाएं हैं, जहां हजारों लोग न्याय पाने के लिए आते हैं और समय पर निर्णय सुनाना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि ये निर्देश किसी भी जज या संस्था पर लांछन लगाने के उद्देश्य से नहीं हैं। झारखंड हाईकोर्ट के फैसलों में देरी होने जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया। किसी कारण से अगर तीन महीने में फैसला नहीं दिया जाता तो पक्षकार के पास आवेदन करने का विकल्प होगा।

क्या अनुच्छेद 142?

अनुच्छेद 142(1) सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार देता है कि वह अपने सामने लंबित किसी भी मामले या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश या निर्देश जारी कर सके, भले ही मौजूदा कानून या प्रक्रिया संबंधी नियम कोई विशेष उपाय प्रदान न करते हों।

सऊदी में 20 साल की जेल, मौत की सजा; 34 करोड़ की 'ब्लड मनी' देकर ऐसे लौटा भारत

नई दिल्ली, एजेंसी। सऊदी अरब में मौत की सजा का सामना करने वाले अब्दुल रहीम 20 साल विदेशी जेल में गुजारने के बाद अपने घर लौट आए हैं। बकरीद के दिन घर लौटने वाले रहीम का उनके घर पर जोरदार स्वागत किया। लंबे समय से परेशान परिवार ने आखिरकार राहत की सांस ली। हालांकि उनकी घर वापसी की राह आसान नहीं थी। सऊदी जेल से उनकी रिहाई की कीमत 34 करोड़ रुपये (15 मिलियन सऊदी रियाल) थी, और 'ब्लड मनी' के रूप में इसे चुकाए जाने के बाद ही वह अपने देश लौट सके। केरल के कोझिकोड के रहने वाले अब्दुल रहीम, जो सऊदी अरब में मौत की सजा का सामना कर रहे थे, उन्हें क्राउड फंडिंग के जरिए जुटाए गए 34 करोड़ रुपये के 'ब्लड मनी' (खून के बदले मुआवजा) का भुगतान करने के बाद रिहा किया गया था। करिपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद, रहीम के रिश्तेदार उसे बाहर तक लेकर आए। वहीं अपनी धरती पर सकुशल वापस देखकर रहीम खुशी में रोने लगे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए मौजूद बिजनेसमैन बॉबी चेम्मनूर ने उन्हें गले लगाया, और रहीम ने वहां जमा हुए लोगों और मीडिया को हाथ हिलाकर अभिवादन किया।

पंजाब निकाय चुनाव में दिखा आप का जादू! 2027 इलेक्शन से पहले जनता ने लगाई मान सरकार पर मुहर

नई दिल्ली, एजेंसी। पंजाब के निकाय चुनावों से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, उसने राज्य की राजनीति का माहौल पूरी तरह बदल दिया है। नगर निगम, नगर कौन्सिल और पंचायत चुनावों में आम आदमी पार्टी को फिर जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। पंजाब की जनता ने एक बार फिर मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी सरकार की नीतियों पर भरोसा जताया है। ये चुनाव केवल स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल है।

सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश गिद्दड़बाहा से आया है, जहां कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राजा वडिंग के गढ़ में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। यह संकेत कांग्रेस के लिए केवल चुनावी हार नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। जनता अब पुराने राजनीतिक ढांचे से आगे बढ़ना चाहती है।

धूरी में तो आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है। 21 में से 20 सीटों पर जीत दर्ज कर पार्टी ने यह साबित कर दिया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के गृह क्षेत्र में जनता का भरोसा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है। इसी तरह हरियाना नगर काउंसिल में 11 में से 7 सीटें जीतकर पार्टी ने बहुमत हासिल किया, जबकि कांग्रेस और भाजपा पीछे रह गईं।

नाभा नगर कौन्सिल के परिणाम भी आम आदमी पार्टी के बढ़ते जनाधार की कहानी कह रहे हैं। भाजपा, अकाली दल और कांग्रेस मिलकर भी वह प्रभाव नहीं छोड़ सके जो आम आदमी पार्टी अकेले छोड़ती दिखाई दी।

कांग्रेस, अकाली, भाजपा को संदेश

कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा तीनों दलों के लिए ये नतीजे गंभीर चेतावनी माने जा रहे हैं। एक समय पंजाब की राजनीति पर राज करने वाले दल आज कई क्षेत्रों में तीसरे और चौथे स्थान के लिए संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं। जनता के बीच यह धारणा मजबूत हुई है कि इन दलों ने वर्षों तक पंजाब को वादों और परिवारवाद की राजनीति में उलझाए रखा, जबकि आम आदमी पार्टी ने व्यवस्था परिवर्तन और विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया।

'सिट्रीन टेरेन' गाउन में जैकलीन फर्नांडिस का स्टनिंग लुक, फ्रेंच रिवेरा के बीच पर दिए सिजलिंग पोज

कान फिल्म फेस्टिवल 12 मई से 23 मई तक चला, जो अब खत्म हो चुका है। वहीं अब फ्रेंच रिवेरा से जैकलीन फर्नांडिस का एक नया लुक सामने आया है, जो किसी के भी होश उड़ा देगा।

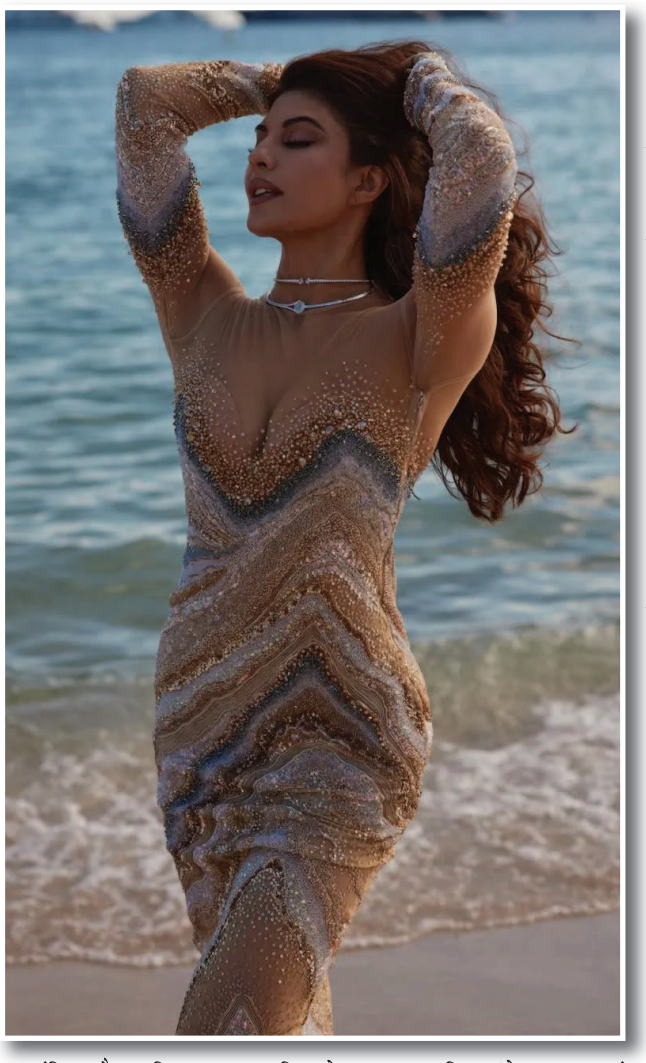

इंडियन फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा के स्टाइलिश गाउन में जैकलीन फर्नांडिस का एक नया लुक सामने आया है। इस नए लुक में जैकलीन ने फ्रेंच रिवेरा के सामने कई सिजलिंग पोज दिए हैं, जो अब फैंस के बीच जमकर वायरल हो रहा है। जैकलीन फर्नांडिस ने अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। इसके साथ ही जैकलीन की कुछ तस्वीरें फैशन डिजाइनर राहुल मिश्रा ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की हैं। जैकलीन की इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार बरसा रहे हैं।

जैकलीन फर्नांडिस के लुक की बात करें तो उन्होंने जो गाउन पहना है, उस पर बारीक धागों की कढ़ाई, क्रिस्टल, मोती और सितारे (सीक्वेंस) जड़े हैं। यह गाउन सिट्रीन (सुनहले) पत्थर की तरह चमकता है। राहुल मिश्रा ने बताया कि यह उनके स्प्रिंग 2026 कॉउचर कलेक्शन 'एल्केमी' का हिस्सा है, जिसका नाम 'सिट्रीन टेरेन' गाउन है। यह डिजाइन धरती के तत्वों और प्रकृति से प्रेरित है। जैकलीन के इस लुक की स्टाइलिंग नमिता अलेक्जेंडर ने की है। वहीं जैकलीन का सटल मेकअप और हेयर शान मु ने किया है। जैकलीन का ये लुक उनके फैंस लाल दिल और फायर इमोजी बना रहे हैं।

जैकलीन फर्नांडिस 2006 की मिस यूनिवर्स श्रीलंका विजेता हैं। श्रीलंकाई, कनाडाई और मलेशियाई मूल के परिवार में जन्मीं जैकलिन ने सिडनी विश्वविद्यालय से जनसंचार में डिग्री हासिल की है। उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान कई सुपरहिट फिल्मों के जरिए बनाई है। जैकलीन ने 2009 में सुजॉय घोष की फिल्म 'अलादीन' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। उन्हें मुख्य रूप से सफलता और लोकप्रियता 'मर्डर 2', 'हाउसफुल 2', 'हाउसफुल 3', 'रेस 2', 'किक' और 'जुड़वां 2' जैसी फिल्मों से मिली है। जैकलीन जल्द ही फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आएंगी। 'वेलकम टू द जंगल' या फिर 'वेलकम 3' एक बहुप्रतीक्षित हिंदी एक्शन-कॉमेडी फिल्म है, जो 26 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है। इस फिल्म का निर्देशन अहमद खान ने किया है।

इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, अरशद वारसी, परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता, जैकलीन फर्नांडीज, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, तुषार कपूर और दिशा पाटनी सहित कई जाने-माने सितारे मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार एक नए भोजपुरी अभिनेता के अवतार में नजर आए। हाल ही में रिलीज हुआ उनका और अक्षरा सिंह का 'घिस-घिस' गाना और डांस काफी चर्चा में है। 'वेलकम 3' फिल्म का निर्माण फिरोज ए. नडियाडवाला द्वारा जियो स्टूडियोज के बैनर तले किया गया है।

फिल्मी सेट पर गढ़ी गई इन सितारों की असल प्रेम कहानी, फिर शादी कर प्यार को दिया मुकाम

पिछले कुछ वर्षों में, बॉलीवुड को प्रतिष्ठित प्रेम कहानियों पर मंथन करने के लिए प्रसिद्धि मिली है। हालांकि, कई बार ये ऑन-स्क्रीन प्रेम कहानियां स्क्रीन से बाहर निकलकर वास्तविक जीवन के रोमांस में बदल गईं, चाहे वह दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह हों या सैफ अली खान और करीना कपूर खान। आइए आज ऐसी ही जोड़ियों और उनकी प्रेम कहानियों पर गौर फरमा लेते हैं-

ऐसा माना जाता है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने फिल्म 'शेरशाह' पर एक साथ काम करना शुरू करने के तुरंत बाद डेटिंग शुरू कर दी थी। हालांकि, कियारा ने 'कॉफी विद करण' के सातवें सीजन में सिद्धार्थ के साथ अपने रिश्ते के बारे में संकेत दिए। अभिनेत्री ने कहा था कि वे दोनों करीबी दोस्त से कहीं अधिक हैं। इसके बाद फरवरी 2023 में इस जोड़ी ने शादी कर अपने प्रशंसकों को तोहफा दिया।

दीपिका-रणवीर

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की पहली मुलाकात फिल्म 'बॉम्बे टॉकीज' के सेट पर हुई थी। हालांकि, दोनों के बीच प्यार की शुरुआत संजय लीला भंसाली की साल 2013 की फिल्म 'गोलियों की रासलीला रामलीला' के दौरान हुई। इसके बाद जोड़ी ने 'पद्मावत' और 'बाजीराव मस्तानी' जैसी फिल्मों में अभिनय किया। रणवीर और दीपिका ने अपने रिश्ते को छिपाकर रखा और 2018 में लेक कोमो में शादी कर ली और अब अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं।

सैफ अली खान और करीना कपूर

सैफ अली खान और करीना कपूर ने भले ही साल 2003 की 'एलओसी : कारगिल' और 2006 की 'ओमकारा' में स्क्रीन स्पेस साझा किया हो, लेकिन दोनों के बीच प्यार की शुरुआत फिल्म 'टशन' के सेट पर हुई। दोनों की कहानी शाही रोमांस निकली। उन्होंने 2008 में अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया। इसके बाद अक्तूबर 2012 में शादी कर ली। जोड़े के दो लड़के तैमूर और जेह अली खान हैं।

आलिया भट्ट- रणबीर कपूर

आलिया भट्ट ने साल 2013 में 'कॉफी विद करण' के एक एपिसोड में सार्वजनिक रूप से रणबीर कपूर पर अपने क्रश की घोषणा की थी। जबकि आलिया अयान मुखर्जी की फैंटेसी फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' के सेट पर रणबीर के करीब आईं। उनकी प्रेम कहानी तब शुरू हुई जब उन्होंने एक साथ फिल्म में काम किया। उनके रोमांस के बारे में अफवाहें 2017 में शुरू हुईं, लेकिन उन्होंने अप्रैल 2022 में शादी होने तक इसे दबाए रखा। उन्होंने नवंबर 2022 में अपनी बेटी राहा का स्वागत किया।

अली फजल-ऋचा चड्ढा

अली फजल और ऋचा चड्ढा की पहली मुलाकात 2012 की कॉमेडी हिट 'फुकरे' के सेट पर हुई थी। डेटिंग शुरू करने से काफी पहले ही अली और ऋचा अच्छे दोस्त बन गए थे। उन्होंने 2015 में एक रिश्ते में प्रवेश किया, और 2017 में इसे आधिकारिक बना दिया। उन्होंने 2020 में शादी कर ली और अब अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com